

बढ़ते वजन से हैं परेशान, तो डेली डाइट में शामिल करें ये फाइबर से भरपूर सब्जियां

परिवहन विशेष न्यूज

बढ़ते वजन से हैं परेशान, तो डेली डाइट में शामिल करें ये फाइबर से भरपूर सब्जियां। इन दिनों बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से लोग मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। वजन मेंटन करने के लिए लोग तरह-तरह के डाइट फॉलो करते हैं। इसके अलावा जिम में घंटों एक्सरसाइज करते हैं। वजन कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास सब्जियों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहेगा।

बढ़ते वजन से हैं परेशान, तो डेली डाइट में शामिल करें ये फाइबर से भरपूर सब्जियां

वजन कम करने के लिए खाएं ये सब्जियां

फाइबर युक्त खाद्य-पदार्थ में कैलोरी की मात्रा कम होती है।

जो वजन कंट्रोल करने में कारगर हैं। पाचन को स्वस्थ रखने में फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वजन को मेंटन रखने में भी मदद करता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर रीच फूड्स शामिल करना चाहिए। फाइबर युक्त खाद्य-पदार्थ में कैलोरी की मात्रा कम होती है। जिससे वजन कम होने में भी मदद मिलती है। अगर आपको कब्ज की समस्या है, तो अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजें खा सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे, जो फाइबर से भरपूर होते हैं, इन्हें खाने से पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है।

ब्रोकोली

ब्रोकोली फाइबर का समृद्ध स्रोत है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन कम होने में मदद मिलती है। आप इसे अपनी डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्रोकोली को सलाद में भी शामिल कर खा सकते हैं या सब्जी और राइस के साथ भी पका कर खा सकते हैं।



कर सकते हैं। गाजर को सब्जी या सलाद के रूप में खा सकते हैं।

हरी मटर

हरी मटर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह प्रोटीन से भरपूर होती है। चाहे तो आप इन्हें सब्जी, करी, परांठे या टिक्की में भी शामिल कर

सकते हैं।

पालक

पालक पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें आयरन, फाइबर और अन्य एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसे खाने से मल त्याग की क्रिया आसान होती है और पाचन भी स्वस्थ रहता है।

बालों के लिए वरदान से कम नहीं है अंडा, हेयर मास्क बनाकर करें इस्तेमाल

परिवहन विशेष न्यूज

संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे.. आपने ये कहावत अक्सर सुनी होगी। कहावत सुनने के साथ-साथ ये भी सुना होगा कि अंडे के सेवन से शरीर को कितना फायदा पहुंचता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को अंडे का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा मानना है कि अंडे में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो शरीर को काफी लाभ पहुंचाते हैं। इसी के चलते डॉक्टर्स भी लोगों को अंडा खाने की सलाह देते हैं।

अंडे के सेवन से बाल आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं लेकिन बहुत से लोग हैं जो अंडे का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे में वो अंडे का हेयर मास्क बनाकर उसे अपने बालों में लगा सकते हैं।



आज के लेख में हम आपको अंडे से कुछ ऐसे हेयर मास्क बनाना सिखाए जा रहे हैं, जो बालों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इन्हें बनाना काफी आसान है, जिस वजह से आप इसे घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं।

अंडा-नारियल तेल

अंडे में तेल या नारियल का तेल मिलाकर एक मास्क तैयार करें। इसे बालों पर लगाने से बालों की नमी बरकरार रहती है। इससे बाल मुलायम हो जाते हैं।

अंडा-जोजोबा ऑयल

इसे बनाने के लिए सबसे पहले अंडे में जोजोबा ऑयल मिलाकर स्मूद सा मास्क बनाएं। कुछ देर लगाने के बाद बालों को सही से धो लें। इसे बालों पर लगाने से बाल मजबूत और चमकदार हो सकते हैं।

अंडा-आंवला

इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले दो अंडों को अच्छे से फेंट कर उसमें आंवले का एक बड़ा चम्मच पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मास्क को अपने बालों पर जड़ से लेकर ऊपर तक अच्छे से लगाएं। ये बालों के लिए काफी फायदेमंद है।

अंडा और एलोवेरा जेल

अंडे में थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाकर आप इसे बालों में लगा सकते हैं। ये बालों के लिए काफी फायदेमंद रहता है।

शादी में Ex की मौजूदगी से हो सकता है बवाल, इसलिए सोच-समझकर करें उन्हें बुलाने का फैसला



परिवहन विशेष न्यूज

एक्स को शादी में बुलाने का फैसला सबका अपना व्यक्तिगत मामला है। इसलिए अगर आप शादी में एक्स को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ पहलु हैं, जिनपर आपको सोच-विचार करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। शादी के बाद जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत दौर शुरू होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी को अपनी शादी में अपने एक्स बायफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहिए ? इस सवाल का कोई सटीक या सही जवाब नहीं है। शादी में एक्स की मौजूदगी आपके खास दिन को बाबाद कर सकती है, जो आमतौर पर होता भी है। इसलिए लोग एक्स को शादी में बुलाने के बारे में सोचते भी नहीं है। एक्स को शादी में बुलाने का फैसला सबका अपना व्यक्तिगत

मामला है। इसलिए अगर आप शादी में एक्स को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ पहलु हैं, जिनपर आपको सोच-विचार करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और शादी में एक्स की मौजूदगी से कुछ गड़बड़ होती है तो ये आपके शादीशुदा जीवन को खराब कर सकता है।

आपसी सहमति से हुआ था ब्रेकअप ?

अगर आपका और आपके एक्स का ब्रेकअप आपसी सहमति और सकारात्मक तरीके से हुआ था तो आप शादी में उन्हें बुलाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स के साथ आपका रिश्ता बुरे मोड़ पर खत्म हुआ था तो ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आपके दिल में अभी भी अपने एक्स के

लिए किसी भी तरह की फीलिंग है तो शादी में उन्हें नहीं बुलाना आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग किसी भी चीज में अड़चन नहीं बनेगी तो भी हम आपको सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। शादी में एक्स की मौजूदगी आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए सोच-समझकर फैसला करें।

शादी में एक्स को बुलाने का फैसला जीवनसाथी से पूछे बिना न लें।

एक्स से ज्यादा जरूरी वो हैं, इसलिए उनसे झजाजत जरूर लें। अगर उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति है तो शादी में एक्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने साथी से ये सवाल करेंगे तब शायद वो मना नहीं करें। लेकिन आप उनके चेहरे के हाव-भाव से इस बात का अंदाजा लगाए और फैसला करें।

सर्दियों में गुलाबी निखार पाने के लिए लगाएं टमाटर के ये फेस पैक, निखरी-निखरी होगी त्वचा

परिवहन विशेष न्यूज

सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को झड़ बनाती हैं और स्किन के ग्लो को कम करती हैं। ऐसे में आप सर्दी के मौसम में नेचुरल तरीके से अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सर्दियों में हमें न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि त्वचा का भी खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को झड़ बनाती हैं और स्किन के ग्लो को कम करती है। जिसके चलते सर्दियों में स्किन का कलर थोड़ी डार्क हो जाती है। हालांकि सर्दियों में स्किन की देखभाल करने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह महंगे प्रोडक्ट होने के बाद भी कई बार हमें मनमुटाबिक रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से सर्दियों में टमाटर का फेस पैक आपकी स्किन के लिए



फायदेमंद साबित होगा। टमाटर में लाइकोपिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है, जो आपकी त्वचा को पोषण देने के साथ ही रंगत साफ करता है। वहीं यह फेस पैक झड़ स्किन की समस्या को दूर करने से साथ स्कुल्लेशन को बढ़ाता है। टमाटर-हल्दी फेस पैक सामग्री

कढ़कूस किया हुआ टमाटर- 2 चम्मच

हल्दी- 1/4 चम्मच

टमाटर और हल्दी का फेसपैक बनाने के लिए 1 मीडियम साइज का टमाटर को कढ़कूस कर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अब इन दोनों को अच्छे

से मिक्स कर फेस और गर्दन पर अप्लाई करें। फिर इस फेसपैक को 20 मिनट तक लगाए रहें और समय पूरा होने के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। यह फेसपैक रंगत निखारने के साथ ही पिंपल्स की समस्या हो भी कम करने में मददगार है। साथ ही इससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहती है।

टमाटर और शहद के फेसपैक की सामग्री

टमाटर का रस- 3 चम्मच

शहद- 1 चम्मच

इस फेसपैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक टमाटर का रस

निकाल लें। फिर टमाटर के रस में शहद को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को 15 मिनट के लिए फेस पर अप्लाई करें। टाइम पूरा होने के बाद फेस को पानी से धो लें। इस फेसपैक से आपकी त्वचा को पोषण मिलता है और स्किन चमकदार बनती है। यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

टमाटर और दही के फेस पैक की सामग्री

टमाटर का रस- 3 चम्मच

दही- 1 चम्मच

इस फेसपैक को बनाने के लिए 3 चम्मच टमाटर के रस में दही मिला लें। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से फेंट लें। अब इस फेसपैक को 15 मिनट के लिए चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें। फिर नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लें। टमाटर और दही से बना यह फेसपैक आपकी त्वचा को पोषण देने के साथ झड़ स्किन की समस्या को दूर करता है। साथ ही यह आपकी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। हालांकि इन फेसपैक को चेहरे पर अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।



पहले ऐसा नहीं था दिसंबर का मौसम, विज्ञानी भी पढ़ रहे मिजाज, किसान बोले - समझ में नहीं आ रहा

● तीन दिन से तापमान में भारी उलटफेर है। शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से डेढ़ डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 14 था।

परिवहन विशेष न्यूज अयोध्या

बूंदबांदी हुई। फिर तेज धूप। अब सुबह से शाम तक रुक रुककर बूंदबांदी होती रही। 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस गिर गया। दिसंबर में मौसम में ऐसा उतार-चढ़ाव कभी-कभी ही दिखाई पड़ता है। कभी ठंड का अहसास होता है, कभी गर्मी लगने लगती है। दिन में चरों और दफ्तरों में पंखे भी चलते हैं। कहीं लोग गर्म कपड़ों में दिखते हैं, कहीं बिना गर्म कपड़ों के। मौसम के इस मिजाज को विज्ञानी भी पढ़ रहे हैं। बताते हैं कि यह उतार चढ़ाव जलवायु परिवर्तन का असर है। इसके नुकसान भी



हैं। दिन में मौसम साफ हो गया। सोमवार को इतनी चटख धूप हो गई कि स्वेटर, जैकेट पहनने वालों को उतारना पड़ गया। रविवार को रात भी मौसम ने करवट ले ली। सुबह से बादल उमड़ने-घुमड़ने लगे। बूंदबांदी शुरू हो गई। तीन दिन से तापमान में भारी उलटफेर है। शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से डेढ़ डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 14 था। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस

ज्यादा रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम 15 था। यह भी सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा रहा। सोमवार को तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह सामान्य से .5 डिग्री सेल्सियस कम। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा है। बूंदबांदी हो रही है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

के मौसम विज्ञानी अमरनाथ मिश्र कहते हैं कि ऐसा कुछ वर्षों पहले नहीं था। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। प्रदूषण बढ़ा है। मौसम पर अलनीनों का प्रभाव पड़ रहा है। जहां बारिश कम होनी है, वहां ज्यादा हो रही है। पहाड़ों पर हवा का दबाव है। मौसम शिफ्ट हो रहा है। बार-बार मौसम में व्यवधान हो रहा है। सारे तथ्य एक साथ प्रभावी हो गए। मौसम में गर्मी बढ़ी तो पहाड़ से हवाएं मैदान की ओर आ गईं। ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन दिसंबर का मौसम पहले जैसा नहीं रहा। इसका दूर तक प्रभाव पड़ेगा।

खेती-किसानी पर भी असर

किसान राम शंकर कहते हैं कि मौसम समझ में नहीं आ रहा है। कभी गर्मी होती है, कभी ठंड बढ़ जाती है। बोआई प्रभावित हो रही है। राम मोहन कहते हैं कि बूंदबांदी के कारण पलेवा वाले खेतों में बोआई के लिए मिट्टी नहीं तैयार हो पा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

बच्चों के विवाद में दो पक्षों में चली गोली, एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

अयोध्या जिले के पूरकलंदर थाना क्षेत्र के अबनपुर सरोहा गांव में मंगलवार सुबह करीब 9-30 बजे बच्चों के विवाद में गोली चल गई। एक को मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। दूसरे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ सरवन सिंह फरार है। विवेक सिंह पुत्र समरजीत सिंह की जिला अस्पताल में मौत हो गई। एक और गंभीर घायल है जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवाद का कारण पुरानी रंजिश व बच्चों का विवाद बताया जा रहा है। गांव में खनाटा छाया हुआ है पुलिस छानबीन कर रही हैं। अखिलेश यादव बोले, इन परिणामों से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया

लखनऊ सा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी पांच राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। ये परिणाम बदलाव के लिए आए थे। जनता केंद्र में भी परिवर्तन चाहती है। इससे भाजपा को चिंतित होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन होता तो वहां परिणाम दूसरा होता। बता दें कि एनपी में कांग्रेस ने सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता बदलाव चाहती थी। 2024 में भी बदलाव के लिए एी वोट पड़ेंगे। भाजपा को इसे लेकर चिंतित होना चाहिए।

खाक फाउंडेशन के तत्वाधान में सेमिनार एवं मुशायरा का कार्यक्रम हुआ, सम्पन्न

परिवहन विशेष न्यूज गाजीपुर

मुहम्मदाबाद नगर की प्रतिष्ठित सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था खाक फाउंडेशन के तत्वाधान में नगर के महल्ला जमालपुर स्थित नौशाद अंसारी के आवास पर मशहूर ओ मारूफ शायर और अदीब स्व खलील अंसारी खाक यूसुफपुरी साहब की 79वीं जन्मतिथि के अवसर पर सोमवार 04 दिसम्बर 2023 को खाक यूसुफपुरी के अदबी कारनामे शीर्षक के तहत सेमिनार एवं मुशायरा का कार्यक्रम का प्रारम्भ आकिब सलेमपुरी के किरात एवं नातपाक से हुई तपश्चात फैजाज अंसारी फैज ने खाक यूसुफपुरी की प्रसिद्ध गजल छबत किल्ली किसी के आने की प्रस्तुत की।

इस मौके पर डॉ सय्यद जफर असलम साहब ने खाक यूसुफपुरी के ऊपर एक मकाला पेश करते हुए उनकी अदबी खिदमत का तत्पसीली जाजापेश किया। मुख्य अतिथि राजकीय सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर के प्रधानाचार्य नियातुल्लाह ने कहा कि खाक यूसुफपुरी एक मुकम्मल



तहरीक थे जिन्होंने समाज को अपनी कलम से राह दिखाई विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रईस अंसारी ने कहा कि सबके यारो मददगार जनाब खाक यूसुफपुरी न केवल अदब बल्कि समाजी और सिपासी मैदान के भी उस्ताद थे। इस अवसर पर आयोजित मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में शायरों और कवियों ने अपने कलाम पेश करके खूब वाहवाही पाई जिनमें खास तौर से गाजीपुर से तशरीफ लाए हन्टर गाजीपुरी, साजिद गाजीपुरी, खालिद गाजीपुरी, बादशाह राही के अलावा दानिश अलबेला बहादुरगंज, नदीम गौलावली, अबू शहमा, दानिश दौलताबादी और मुकामी शोअरा डॉ सय्यद जफर असलम, डॉ राशिद रब्बानी, आसी यूसुफपुरी, अहकम गाजीपुरी, सी पी सुमन, आकिब

सलेमपुरी, सरवर मोहम्मदाबादी, इरशद जनाब खलीली, वकील अरकम ने अपने कलाम पर खूब दादो तहसीन और तालियाँ बटोरी। इस अवसर पर उपस्थित सम्मानित श्रोताओं में मोहम्मद हुसैन एम डी भाई, शादाब कादरी, डॉ वसीम अख्तर, डॉ शाहिद जमाल गुरु प्रजापति, सुल्तान अहमद, आसिम इरफान, सुहेल मुस्ताज, रईस फरीदी, साजिद अंसारी, इररार अंसारी, इजहार अंसारी, अनीस अंसारी, माज अकरम मोईन, अब्बास, वसीम, बड़े पहलवान, अफजाल, सैफ, जाहिद, आदिल, बबलु, यूसुफ, यावर फैसल इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन इरशद जनाब खलीली ने किया। अध्यक्षता डॉ साजिद गाजीपुरी ने किया अंत में सभासद कैफ अंसारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा की मनाई गई पुण्यतिथि मनाई

सोनभद्र। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन सोनभद्र द्वारा जनपद मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत लोढ़ी के पंचायत भवन पर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा की पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई साथ ही लोढ़ी गांव के निवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिनका 3 दिसंबर को असामयिक निधन हो गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने कहा कि, शर्मा जी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके द्वारा पंचायत को अधिकार दिलाने के लिए कई बार विधानसभा एवं लोकसभा पर प्रधानों को एकजुट करके आवाज बुलंद की गई जिसके कारण 73वां संविधान संशोधन शमशेर बहादुर सिंह, जिला सचिव सत्य प्रकाश पांडे, जिला प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान राजकुमार बौद्ध, रावटसगंज के ब्लॉक अध्यक्ष आनंद कुमार पटेल, कर्मा के ब्लॉक अध्यक्ष मुन्ना मौर्य, चतरा के ब्लॉक अध्यक्ष नीरज सिंह, नगवा के ब्लॉक अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह, घोराल से पंकज दुबे आदि लोग उपस्थित रहे।

जुबिलेंट फूडवर्क्स ने पोल्ट्री सोर्सिंग में भारत की पहली नो एंटीबायोटिक्स एवर की उपलब्धि हासिल की

● अविनाश कांत कुमार, प्रेसिडेंट- वैल्यू चेन इजीनियरिंग, हॉन्ग्स किचन, इंटरनेशनल बिजनेस और सीएसआर- ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने कहा

परिवहन विशेष न्यूज नोएडा

जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी फूडसर्विस कंपनी ने पोल्ट्री बर्ड्स के हेल्थ मैनेजमेंट में भारत की पहली नो एंटीबायोटिक्स एवर पॉलिसी 2023 को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। यह महत्वपूर्ण पॉलिसी खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण के लिये जेएफएल की प्रतिबद्धता दिखाती है। कंपनी एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस से जुड़ी दुनिया भर की चिंताओं को हल करने की कोशिश कर रही है।

कंपनी नवंबर 2017 से सक्रिय तौर पर एंटीबायोटिक्स पॉलिसी पर काम कर रही है, ताकि पोल्ट्री सोर्सिंग में एंटीबायोटिक्स के गलत

इस्तेमाल को रोका जा सके। तीनों सुनियोजित चरणों के सफल क्रियान्वयन में नैतिक व्यवहारों, वेटेरिनेरी निगरानी में इलाज के लिये इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक्स पर रोक और वृद्धि बढ़ाने के लिये गैर-उपचारात्मक इस्तेमाल को रोकने पर जोर दिया गया है। इस उपलब्धि पर अपनी बात रखते हुए अविनाश कांत कुमार, प्रेसिडेंट- वैल्यू चेन इजीनियरिंग, हॉन्स किचन, इंटरनेशनल बिजनेस और सीएसआर- ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने कहा, जुबिलेंट फॉर ऑल ग्राहकों को दिए जाने वाले महत्व को लेकर कंपनी की प्रतिबद्धता दशतां है। हम ना केवल हमारे ग्राहकों को बल्कि प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं।

कंपनी के बिजनेस मॉडल में कई हितधारक शामिल हैं और यह सभी को फायदा पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

यह उपलब्धि जिम्मेदार सोर्सिंग को और भी मजबूत बनाने में लंबे समय तक काम करेगी और यह

हमारे सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। क्यूएसआर की दुनिया में एनएई पॉलिसी बनाने में सबसे आगे हैं, और एंटीबायोटिक्स को छोड़ना केवल एक नीति नहीं है यह हमारे मूल्यों की पुष्टि करता है। यह हमारे समझदार उपभोक्ताओं के लिये उच्च-गुणवत्ता के, सुरक्षित एवं नैतिकता से सांस किये गये उत्पादों की आपूर्ति की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नो एंटीबायोटिक्स एवर की उपलब्धि हासिल करने के लिये कंपनी ने मजबूत सर्विलांस और सुपरविजन सिस्टम, बड़े-बड़े खेतों, बूचड़खानों और प्रसंस्करण इकाइयों पर क्रियान्वयन किया है। इस व्यापकप्रणाली पर योग्य वेटेरिनेरियंस की नजर रहती है और यह एंटीबायोटिक यूसेज पॉलिसीके कठोर अनुपालन की गारंटी देती है। इसके अलावा, कंपनी ने फार्म ट्रेसिबिलिटी की अनूठी उपलब्धि हासिल की है, जो उत्पादों की जिम्मेदारी से सोर्सिंग और निगरानी के लिये उसकी प्रतिबद्धताको सत्यापित करती है।

दलित साहित्य में है नए मानवीय एवं समतामूलक सामाजिक मूल्यों का समावेश : श्रीमती शकुन सिंह

परिवहन विशेष न्यूज गाजीपुर

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर में पूर्व शोध प्रबन्ध प्रस्तुत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी महाविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ तथा विभागीय शोध समिति के तत्वाधान में महाविद्यालय के सेमिनार हाल में सम्पन्न हुई, जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापक, शोधार्थी व छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे। उक्त संगोष्ठी में भाषा संकाय के हिन्दी विषय की शोधार्थिनी श्रीमती शकुन सिंह ने अपने शोध शीर्षक हिन्दी दलित साहित्य में समकालीन सामाजिक यथार्थ र नामक विषय पर शोध प्रबन्ध व उसकी विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य का अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि दलित चेनना और दलित विमर्श के दर्शन सदैव होते रहे



हैं। आधुनिक काल में तो दलित विमर्श एक विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आई है। दलित साहित्य के केंद्र में भारतीय समाज का सबसे निचला तबका, मेहनतकश सर्वहारा मानव जाति है, जिसे सदियों से धर्मशास्त्र एवं सामाजिक परंपरा की आड़ में शारीरिक एवं मानसिक रूप से गुलाम बना कर रखा गया और दलित समाज जितना उपेक्षित रहा, उतना ही उनका साहित्य भी उपेक्षित रहा है। दलित समाज और दलित साहित्य ने अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए निरंतर

संघर्ष किया है। अपनी इसी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए दलित साहित्य प्रतिबद्ध भी है, क्योंकि दलित साहित्य में नए मानवीय एवं समतामूलक सामाजिक मूल्यों का समावेश है। प्रस्तुतिकरण के बाद विभागीय शोध समिति, अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ व प्राध्यापकों तथा शोध छात्र-छात्राओं द्वारा शोध पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिनका शोधार्थिनी श्रीमती शकुन सिंह ने संतुष्टिपूर्ण एवं उचित उत्तर दिया। तत्पश्चात समिति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफे० (डॉ०)

राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने शोध प्रबंध को विश्वविद्यालय में जमा करने की संस्तुति प्रदान किया। इस संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफे० (डॉ०) राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय, अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के संयोजक प्रोफे० (डॉ०) जी० सिंह, शोध निदेशक एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफे० (डॉ०) विनय कुमार दुबे , डॉ० संजय चतुर्वेदी, प्रोफे० (डॉ०) अरुण कुमार यादव, डॉ० कृष्ण कुमार पटेल, डॉ० राम दुलारे, डॉ० योगेश कुमार, डॉ० हेमन्त सिंह, डॉ० समेन्द्र नाथ मिश्र, प्रोफे० (डॉ०) सत्येंद्र नाथ सिंह, डॉ० डॉ० अतुल कुमार सिंह एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकगण तथा शोध छात्र- छात्राएं आदि उपस्थित रहे। अंत में प्रोफे० (डॉ०) विनय कुमार दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के संयोजक प्रोफे० (डॉ०) जी० सिंह ने किया।

स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते फल फूल रहे मानक विहीन पैथोलॉजी सेंटर

परिवहन विशेष न्यूज गाजीपुर

बिरनो। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो के ठीक सामने अवैध ढंग से पैथोलॉजी लैब चला रहा है जिसके आड़ में अल्ट्रा साउंड भी हो रहा है। खास बात यह है कि समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने संचालित पैथोलॉजी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग इतना मेहरबान है कि पूर्व में औचक निरीक्षण करने पहुंचे सौम्यओ देश दीपक पाल और क्षेत्रिय विधायक वीरेंद्र यादव से भी क्षेत्रीय सम्मानित जनों ने शिकायत करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण अवैध ढंग से रिया पैथोलॉजी संचालित हो रहा है और मनमाना चार्ज भी वसूल रहा है जिसमें अल्ट्रासाउंड का भी कार्य किया जाता है अवैध ढंग से संचालित इस पैथोलॉजी



पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान क्यों है इसको लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 6 महीने से संचालित पैथोलॉजी की मिलीभगत से कार्य कराया जा रहा है इतना नहीं क्षेत्र में फर्जी हॉस्पिटलों की भी भरमार है लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिना किसी छापेमारी के जिलाधिकारी आर्यका अखोरी के आदेश के बाद भी चुपी साधे हुए हैं जिससे आम जनमानस का अवैध ढंग से संचालित अस्पताल और बिरनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के

समीप संचालित रिया पैथोलॉजी शोषण करने में जुट हुए। इस संबंध में बिरनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक सीपी मिश्रा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड और अवैध ढंग से संचालित इस पैथोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं थी शासनादेश के अनुसार आतिश शीघ्र कार्रवाई कर रिपोर्ट जिले पर भेज दिया जाएगा अहम बात यह है कि इसकी जानकारी अधिकारियों की भी है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे।

खिना रुके 20 घंटे तक हुई बारिश ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, पर बीती रात रही बेहद गर्म

● वर्ष 2022 में तो एक मिमी से कम बारिश हुई थी। 2014, 2015 और 2019 में क्रमशः 13.4, 14.3 और 16 मिमी बारिश हुई थी। 2011-12-16 और 2020 में बारिश हुई ही नहीं थी। अन्य वर्षों में 10 मिमी से कम रही।

परिवहन विशेष न्यूज लखनऊ

मिचौंग तूफान का असर राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में देखने को मिला। यहां सोमवार को रिकॉर्ड बारिश हुई। आने वाले एक-दो दिनों में बारिश का असर बना रह सकता है। चक्रवातीय दबाव के चलते राजधानी में रविवार देर रात करीब ढाई बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला 20 घंटे तक चला। इस दौरान हुई 17 मिमी बारिश ने दिसंबर में पानी गिरने का बीते 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

न्यूनतम तापमान ने भी रिकॉर्ड बनाया और बीते सालों में पांचवीं सबसे गर्म रात रही। दिन और रात के पारे का अंतर घटकर दो डिग्री के आसपास रह गया। दिन का पारा

19 और रात का 17 डिग्री रहा। बारिश का असर सामान्य जनजीवन पर दिखा।

आंचलिक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मंगलवार से मौसम खुलने के आसार हैं।

सोमवार सुबह जब लोग नींद से जागे तो तेज बारिश जारी थी। सुबह दस बजे के आसपास मौसम साफ हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बारिश होने लगी जो रात नौ बजे तक जारी रही। शाम तक रिकॉर्ड हुई 17 मिमी बारिश बीते 12 वर्षों में दिसंबर

में सर्वाधिक रही। वर्ष 2022 में तो एक मिमी से कम बारिश हुई थी। 2014, 2015 और 2019 में क्रमशः 13.4, 14.3 और 16 मिमी बारिश हुई थी। 2011-12-16 और 2020 में बारिश हुई ही नहीं थी। अन्य वर्षों में 10 मिमी से कम रही।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रात बीते वर्षों में पांचवीं सबसे गर्म रात रही। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा। इससे पहले छह दिसंबर 2021 को यह 18.2, तीन दिसंबर 2021 को 17.5, 25 दिसंबर 1980 में 17.3, दो दिसंबर 2015 में 17.1 रहा था।

बारिश ने राजधानी की हवा सुधार दी। सोमवार शाम को औसत एक्यूआई 93 रहा, जो इस सीजन में सबसे कम रहा। लालबाग में एक्यूआई 131 और तालकटोरा में 119 आ गया। यह केंद्रीय विद्यालय के पास 84, कुकरेल पिकनिक स्पोर्ट के पास 62 और डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के पास 71 रहा।



कार से सफर को आसान बनाते हैं ये पांच एक्सटीरियर फीचर्स, जानें किस तरह करते हैं काम

परिवहन विशेष न्यूज

लोगों को सबसे ज्यादा कार से सफर करना अच्छा लगता है। साथ ही कार से सफर के दौरान कौन से पांच एक्सटीरियर फीचर्स मदद करते हैं। आइए जानते हैं।

अक्सर लोग अपनी कारों को अलग दिखाने के लिए कुछ एक्सेसरीज और पाटर्स लगवाते हैं। लेकिन इनमें से पांच ऐसे पाटर्स हैं जिनके कारण सफर के दौरान काफी आसानी होती है। हम इस खबर में आपको ऐसे पांच एक्सटीरियर पाटर्स की जानकारी दे रहे हैं। जिनसे सफर काफी आसान हो जाता है।

अलॉय व्हील्स

कारों में अलॉय व्हील्स का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। कंपनियों की ओर से कारों के टॉप वैरिएंट्स में अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। वहीं जिन कारों में स्टील रिम दिए जाते हैं, उनमें भी ग्राहक बाजार में मिलने वाले अलॉय व्हील्स लगवाते हैं। यह ना सिर्फ दिखने में काफी स्टाइलिश होते हैं, बल्कि स्टील रिम के मुकाबले इनका वजन भी कम होता है। जिससे कार चलाते हुए ड्राइवर को बेहतर अनुभव मिलता है।

बोनट हुड



कुछ एसयूवी में कंपनियों की ओर से बोनट के ऊपर एक हुड लगाया जाता है। देखने में यह भले ही स्टाइलिश लगता है लेकिन इसका असल काम किसी को नहीं पता होता। ज्यादातर बड़े इंजन वाली कारों और एसयूवी में बोनट के ऊपर एक उभार मिलता है। जो लोगों को स्टाइलिश लगता है, लेकिन इस उभार को हुड कहा जाता

है। जिसका काम इंजन को अतिरिक्त हवा पहुंचाना होता है। बड़े इंजन की कारों और एसयूवी को कई बार ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, जिससे इंजन के तापमान को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में हुड के जरिए कारों को अतिरिक्त हवा मिलती है। इंजन तक हवा पहुंचाने के साथ ही यह गर्म हवा को बाहर निकालने का काम भी करता है।

लगता है बल्कि इससे एसयूवी या एमपीवी ज्यादा स्टाइलिश भी लगती हैं। इनका सही उपयोग केरियर लगाने या सामान रखने में होता है। एक बार छत पर

रूफ रेल ज्यादातर एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट के वाहनों में ही रूफ रेल लगाई जाती हैं। इससे ना सिर्फ वाहन ज्यादा ऊंचा

सामान रखने के बाद आसानी से रस्सी का उपयोग कर रूफ रेल के साथ बांधकर सामान को आसानी से ज्यादा दूरी तक ले जाया जा सकता है।

डीआरएल

डीआरएल को डे टाइम रनिंग लाइट भी कहते हैं। यह किसी भी वाहन में आगे की ओर हैडलाइट या

उसके आस-पास लगाई जाती हैं। दिन हो या रात, यह हमेशा जलती रहती हैं। जब भी वाहन को ऑन किया जाता है तभी यह जल जाती हैं और जब वाहन को बंद किया जाता है, तभी यह बंद होती हैं। यह सड़क पर आपकी मौजूदगी को दिखाकर हादसों से बचाने का काम करती हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह सिर्फ आकर्षक लगती है।



CNG Bike लाने की तैयारी में Bajaj, Pulsar को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

बजाज ऑटो सीएनजी मोटरसाइकिलें लॉन्च करके एंट्री-लेवल दोपहिया सेगमेंट में हलचल मचाने पर विचार कर रहा है, जिससे ग्राहकों के लिए ईंधन की कीमतें लगभग 50% तक कम हो जाएंगी। एक साक्षात्कार में, प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने आश्चर्य जताया कि सीएनजी स्कूटर या मोटरसाइकिल क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा कि निमाताओं के लिए सुरक्षा, रेंज, चार्जिंग और बैटरी लाइफ से संबंधित कोई चिंता नहीं होगी और ऐसी बाइक उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी होगी। बजाज ने कहा कि प्रवेश खंड, जो कि 100 सीसी मोटरसाइकिल है, समग्र रूप से उद्योग के लिए दबाव में बना हुआ है। उन्होंने कहा, हरिप्रसिद्ध के निचले स्तर के खरीदार जो कोविड, नौकरी छूटने और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हुए थे, वे वापस नहीं आ रहे हैं। बजाज ऑटो के पास एंट्री सेगमेंट में 100 और 125 सीसी के बीच सात मोटरसाइकिल मॉडल हैं, और वह इस श्रेणी में अग्रणी नहीं है। हालांकि, सीएनजी



थी-व्हीलर सेगमेंट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है। बजाज ऑटो के एमडी ने इस वित्तीय वर्ष में पल्सर मोटरसाइकिल के छह नए अपग्रेड और अब तक की सबसे बड़ी पल्सर लॉन्च करने

वर्तमान में सबसे बड़ा पल्सर 250 वैरिएंट है। बजाज ने कहा कि कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल और चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन भी बढ़ा रही है। ट्रायम्फ का उत्पादन वर्तमान में लगभग

8,000 इकाइयों से बढ़कर 15,000-20,000 इकाई प्रति माह और चेतक का त्योहारी सीजन के दौरान लगभग 10,000 इकाई प्रति माह और वर्ष के अंत तक लगभग 20,000 इकाई हो जाएगा। कंपनी अक्टूबर में ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों का निर्यात भी शुरू कर देगी। इसके अलावा, बजाज ऑटो सक्रिय रूप से प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अवसर तलाश रहा है, जिसमें लगभग 1.7 लाख रुपये की कीमत वाली बाइक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रीमियम सेगमेंट में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है। यह एंट्री-लेवल सेगमेंट की तरह नकारात्मक नहीं है, लेकिन मध्य-सेगमेंट जितना बड़ा या मजबूत नहीं है। हमारे पास पल्सर आरएस, डोमिनार, केटीएम, दुश्कवर्न और अब ट्रायम्फ जैसे कुछ ब्रांड हैं। मैं कहूंगा कि हम वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं।

Upcoming Toyota Car: जल्द आ रही है टोयोटा की अर्बन क्रूजर टैसर

परिवहन विशेष न्यूज

टायसर टोयोटा की सबसे किफायती एसयूवी होगी, यह देखते हुए कि ब्रेजा पर आधारित अर्बन क्रूजर बिक्री पर नहीं है और नई ब्रेजा रिलीज के साथ इसे रेंज में शामिल नहीं किया गया है। टोयोटा की अगली नई कार अर्बन क्रूजर टैसर होगी, जिसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। कार को अपने मारुति समकक्ष के साथ कैसे रखा जाएगा, इसके बारे में कुछ बदलाव हो सकते हैं। टायसर टोयोटा की सबसे किफायती एसयूवी होगी, यह देखते हुए कि ब्रेजा पर आधारित अर्बन क्रूजर बिक्री पर नहीं है और नई ब्रेजा रिलीज के साथ इसे रेंज में शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक अर्बन क्रूजर टैसर मारुति फ्रॉक्स पर आधारित होगा लेकिन टर्बो बूस्टरजेट को छोड़कर केवल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की पेशकश कर सकता है। हां, अर्बन क्रूजर टैसर में ऑटोमैटेड



मैनुअल ट्रांसमिशन (एमटी) और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मानक 1.2 लीटर पेट्रोल की सुविधा हो सकती है, जबकि बूस्टरजेट फ्रॉक्स के लिए विशेष रूप से उपलब्ध रह सकता है। टैसर की शैली फ्रॉक्स की तुलना में अलग होगी, जिसमें फ्रंट-एंड में बदलाव और संभवतः नए मिश्र धातु के पहिये शामिल होंगे। जबकि टैसर और फ्रॉक्स के बीच स्टाइल में बदलाव ग्लैंजा/बलेनो की तुलना में महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन वे ग्रैंड विटारा/हाइडर के बीच उतने व्यापक नहीं होंगे। उम्मीद है कि इंटीरियर वही रहेगा लेकिन नए इंटीरियर रंग के साथ आ सकता है। अर्बन क्रूजर टैसर में फ्रॉक्स

की तुलना में कम उपलब्ध ट्रिम्स हो सकते हैं। फ्रॉक्स लाइनअप के भीतर, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन अपनी कीमत के कारण अधिक लोकप्रिय रहा है, जिससे यह मारुति रेंज में ब्रेजा के साथ साल की शुरुआत में आएगा, तो अर्बन क्रूजर टैसर फ्रॉक्स से अधिक महंगा होने की उम्मीद है। टोयोटा ने हाल ही में भारत में नई वेलफायर लॉन्च की है, जबकि मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी में इसकी रेंज बड़े पैमाने पर बाजार क्षेत्र पर कब्जा करती है।

बिना खरीदे इन शहरों में आप दौड़ा पाएंगे Royal Enfield की बाइक्स



परिवहन विशेष न्यूज

रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी मोटरसाइकिल रेंटल पहल शुरू की है, जिसका नाम रॉयल एनफील्ड रेंटल है। यह कार्यक्रम 40 से अधिक मोटरसाइकिल रेंटल ऑपरेटरों के साथ सहयोग करके भारत के 25 शहरों में मोटरसाइकिल किराये की सुविधा प्रदान करेगा। रॉयल एनफील्ड रेंटल के पास किराए के लिए उपलब्ध 300 से अधिक मोटरसाइकिलों का बेड़ा होगा। रॉयल एनफील्ड रेंटल अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, धर्मशाला, लोह, मनाली, हरिद्वार और नरपिकेश जैसे शहरों में उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, निमाता अपनी मोटरसाइकिल किराये की सेवाओं का विस्तार उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, गोवा, कोच्चि, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, शिमला, नैनीताल, बीर बिलिंग, सिलीगुड़ी और देहरादून तक करेगा। कंपनी का कहना है कि वह अपनी विस्तार योजनाओं के तहत इस रोस्टर में और अधिक शहरों को शामिल करने का इरादा रखती है। किराये की रॉयल एनफील्ड बाइक कैसे बुक करें ? मोटरसाइकिल किराए पर लेने के लिए रॉयल एनफील्ड रेंटल वेबसाइट पर जाएं। वह शहर चुनें जहां आपको मोटरसाइकिल की

आवश्यकता है। फिर, पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ तिथियां और समय चुनें। वेबसाइट आपको उपलब्ध मॉडल और उनकी कीमतें दिखाएगी। आप एक फॉर्म भरकर ऑपरेटर का योग्य थुलक लिया जा सकता है। इस नई पहल के बारे में बोलते हुए रॉयल एनफील्ड के मुख्य ब्रांड अधिकारी मोहित धर जयाल ने कहा कि मोटरसाइकिल किराये और दूर ऑपरेटरों और मैकेनिकों के हमारे विस्तारित परिवार ने हमारी संस्कृति को आकार देने और शुद्ध मोटरसाइकिल के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए Tata Motors ने बनाया खास प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की रणनीति के तहत टाटा मोटर्स लिमिटेड भारत में विशेष डीलरशिप बनाने की प्रक्रिया में है, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। कंपनी के यात्री वाहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्यवसाय के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, हमें ईवी के लिए एक अलग ब्रांड दर्शन और व्यक्तित्व बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और हम आने वाली तिमाहियों में विशेष ईवी डीलरशिप के लिए जाना शुरू करेंगे। टाटा मोटर्स अपनी नई ब्रांड पहचान चंद्रोई के तहत अलग, विशेष इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खुदरा शोरूम स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी, जिसने गुरुवार को बाजार की अग्रणी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) नेक्शॉन का नया संस्करण (14.74 लाख रुपये की कीमत) का अनावरण किया, ने पिछले महीने ईवी के लिए अपनी नई ब्रांड पहचान पेश की।

नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ एक गोलेमैज चर्चा के दौरान चंद्रा की टिप्पणियों के अनुसार, प्रारंभ में, टाटा चंद्रोई ब्रांड वाले इलेक्ट्रिक



वाहनों को समर्पित कुछ खुदरा दुकानें स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसे अगस्त में पेश

किया गया था। कंपनी अपनी अंतरराष्ट्रीय रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी है, जिसमें

इरादा वर्ष 2027 तक बैटरी चालित मॉडल के विकास के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर आवंटित करने का

संभावित रूप से इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात शामिल हो सकता है, हालांकि, विशिष्ट लक्ष्य बाजारों का खुलासा नहीं किया गया था। टाटा का

है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने पिछले महीने भारत में टिगोर, नेक्शॉन और टियागो ईवी मॉडल सहित 4,613 इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 65% की वृद्धि है।

ऑटोमेकर पश्चिमी राज्य गुजरात में एक बैटरी फैक्ट्री के निर्माण के साथ अपनी घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 20 गीगावाट घंटे होने का अनुमान है। भारत में लिथियम-आयन सेल बनाने की योजना वाली अन्य कंपनियों में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट और रिलायंस ईंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। कथित तौर पर, चंद्रा के अनुसार, टाटा विकसित नियमों को समायोजित करना जारी रखेगा, जिन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत स्ट्रेज 7 उत्सर्जन नियम की शुरुआत के साथ डीजल मॉडल की बिक्री में और गिरावट आने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में टाटा के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में डीजल मॉडल की हिस्सेदारी 16% थी।



यह चुनाव भारत को मजबूती देने वाले हैं

भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने न केवल मतदाता के जागरूक होने का संकेत दिया है बल्कि भारत को भारतीय मूल्यों के अनुरूप विकसित होते देखने की उसकी मंशा को भी उजागर कर दिया है, इसलिये इन चुनावों में तुष्टीकरण, साम्प्रदायिकता, जातीयता के बजाय विकास एवं विकसित भारत के नाम वोट पड़े। मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है उससे एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि भारत में लोकतंत्र कायम है और इसकी जीवन्तता के लिये मतदाता जागरूक है। मतदाता को ठगना या लुभाना अब नुकसान का सौदा है। इन चुनावों में मोदी लहर बरकरार रही, भले ही आप श्रेय चाहे हल्लाड़ली बहानाह्म को दें, तीन तलाक को दें, तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को दें, सनातन मूल्यों को दे। देश में पहली बार एक दल के नाम पर चुनाव हुए, नये भारत-सशक्त भारत के नाम पर चुनाव हुए, इन चुनावों में व्यक्ति गौण हो गए। ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण एवं उत्साह वाले इसलिये बने कि इन्हीं चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा था। उस लिहाज से निरस्रंदेह तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड एवं स्पष्ट ऐतिहासिक जीत बहुत बड़ी है और बहुत कुछ बर्‍या कर रही है। अगले लोकसभा चुनाव से चार माह पहले हुए इन विधानसभा चुनावों को सत्ता का समीपाइल माना जा रहा था। उसी नजरिये से देखें तो यह समीपाइनल मुकाबला लगभग एकतफा नजर आता है। उत्तर भारत के तीनों राज्यों में भाजपा ने जबर्दस्त जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण भारत के एक और राज्य में कांग्रेस सत्ता पाने में सफल रही है। लेकिन वहां भी भाजपा का एक सीट से 8 तक पहुंचना भाजपा के लिये शुभता का संकेत है। आज भी किसी दल के नेता में यह क्षमता नहीं है कि देश की बजाय पार्टी के ध्वज तले आगे बढ़ सके, वे ही दल एवं नेता प्रभावी हैं जो देश के अस्तित्व एवं अस्मिता को नये शिखर देने के संकल्पबद्ध हैं, न कि षड्यंत्रपूर्वक किन्हीं अल्पसंख्यकों को एक दल-विशेष को वोट देने को उकसा रहे हैं। जनता ने परिवारवादी सोच को नकार दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जमीन पर सच देखने को मतदाता आतुर है, राष्ट्र को तोड़ने की साजिशों पर भी मतदाता सतर्क एवं सावधान हुआ है। अगले लोकसभा चुनावों में अधिक समर्थन बाकी नहीं है। जनता की आंखें सरकारों के कामकाज पर टिकी हुई रहेंगी। कई प्रकार की अपेक्षाएं बाट जोह रही हैं। लघु जनादेश ही बड़े जनादेश का आधार बनता है। इसलिये इस बार का जनादेश विशेष है, जनता के मन में क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। पिछले सरकारों के दौर में सत्ता-संचर्ष के चलते जाति-धर्म और सम्प्रदायों के नाम पर देश पीछे जा रहा था, विकास अवरुद्ध था, निवेश ठहरा हुआ था, रोजगार खो गया था, देश के भीतर एवं सीमाओं पर आतंकवाद को पनपाया जा रहा था, हिंसा एवं आतंकवादी घटनाओं से देश की आत्मा लहलुहान थी। कोई नए भारत का, औद्योगिक भारत का सपना नहीं देख रहा था। राष्ट्रवाद की चर्चा करना पग जैसा लगता था। इन हालातों को बदलने के लिये मोदी-संकल्पों ने फिजां ही बदल दीं। दलों से ऊपर उठकर देशहित, राष्ट्रीयता, विकास एवं आमजन सर्वोपरि हो गया है, इसकी सार्थक निष्पत्तियां एवं स्वर लहरियां इन चुनावों परिणामों में सुनी जा सकती है। दरअसल, तीन राज्यों में हार से कांग्रेस की राजनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। यह हार अपने आप में बड़ा सदमा है, कांग्रेस की सत्ताकांक्षा एवं उससे जुड़ी परिवारवादी सोच, बड़बोलापन, मुक्त रेवड़ियों का सहारा, मोदी विरोध के नाम पर घटिया शब्दावली का प्रयोग, ऐसे कारणों की समीक्षा कांग्रेस को करनी ही पड़ेगी। भाजपा की जीत का श्रेय मोदी को जाता है, पर कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आसन्न चुनौती अगले लोकसभा चुनाव और विपक्षी गठबंधन हॉइडियाह्म के आंतरिक समीकरण होगा। नया विपक्षी गठबंधन बनने के चंद महीने में हुए इन विधानसभा चुनावों में एकजुटता के बजाय अंतर्विरोधों का ही संदेश गया और बहुत कर्कश स्वर में गया। इन चुनाव परिणामों से न केवल कांग्रेस बल्कि समूचे विपक्ष के नेताओं को सीखना होगा, सबक लेना होगा। लोकलुभावन योजनाएं एवं मुफ्त-संस्कृति काम नहीं आयेगी। महत्वाकांक्षा एवं सबसे पुरानी पार्टी होने के अहंकार से बाहर आना होगा। बुनियादी स्तर पर संगठन और आम जनता के बीच जाकर विश्वास जीतना होगा, नीति एवं नियत को बदलना होगा। भारत की राजनीति एक नये बदलाव की ओर अग्रसर है, उस बदलाव के बिन्दुओं को स्वीकारना होगा। तीन राज्यों की ऐतिहासिक जीत ने भाजपा का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। भाजपा एवं मोदी की सोच, नीतियां, योजनाएं एवं दृष्टिकोण भी उनको अधिक साहसित एवं मनबबली बनायेंगे। उनके आदिवासी विकास का संकल्प, महिलाओं की भूमिका और 33 प्रतिशत आरक्षणा का आश्वासन, समान नागरिक संहिता, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, युवाओं के लिये रोजगार, विश्वगुरु बनाने की कार्ययोजना, देश की सुरक्षा एवं सशस्त्र जैसे गंभीर मुद्दों के निस्तारण के लिए भी मोदी ही दम रखते जान पड़ते हैं। देश को आगे बढ़ाना है तो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से मुक्त होना आवश्यक है। मोदी ही गारण्टी की गारण्टी हैं, लेकिन इसमें अहंकार नहीं है, मोदी ने अपनी जगह छटी एवं देश की जनता को ही प्रमुखता दी, देश की जनता को हमेशा आगे रखा है।

कमाल की इंसानियत



डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

आज के समय में इंसानियत ढूँढना मतलब पानी पर पानी लिखने जैसा काम है। काशा इंसानियत का नाम महंगाई होता हर जगह देखने को मिल जाती। मगर वो कहते हैं न, कि जब जब लोगो का इंसानियत पर से विश्वास उठा है, तब तब कोई न कोई सच्चा इंसान सामने आकर इंसानियत का अलख बनकर जल उठता है। बहरहाल आज हम आपको एक ऐसी ही इंसानियत की निशानी वाली कहानी से रूबरू करवाना चाहते है। ये इंसानियत की कहानी उन हजारों बेरहमों के लिए एक मिसाल है, जो आज भी इंसानियत का खून करते हैं। चुनाव का मौसम था रिक्शा चलाने वाले रामू काका कड़ी दुपहरिया में पेट पालने के लिए मजबूर थे। बदन ऐसा कि उनका साथ नहीं दे रहा था। इसी रिक्शा से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, काबिल बनाया, बच्चे थे कि उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जब से सॉप आस्तिन में ज्यादा और धरती पर कम रहने लगे हैं, तब से ये घटनाएँ आम हो चली हैं। रामू काका हमेशा रोया करते थे। बच्चों ने उन्हें दूध में से मक्खी को तरह बाहर कर दिया था। एक वक्त था उनके लिये पैसे मांगने नहीं रखते। बच्चों को ही सब कुछ समझते थे। बच्चे थे कि पैसों के सिवाय किसी और चीज को नहीं समझते थे। उन्होंने सौता भी नहीं था एक दिन ऐसा आयाज जब उनके पास न पैसे होंगे ना ही कोई काम। ऐसे में हाथ जोड़ते हुए एक दिन एक आदमी आया और उसने बिना किसी सवाल-जवाब के अगले दो महीने के लिए रामू काका के खाने-पीने और दूसरी जरूरतों की जिम्मेदारी ले ली। उसे पता था की रामू काका बेसहारा हैं पर उसने काका की आंखो का दर्द देख लिया था। उसको लोगो ने कहा कि तुम काका की मदद क्यों करते हो उन्हें तो उनके बेटे तक ही पुछो। ऐसे में तुम क्यों तकलीफ उठाते हो। आदमी था कि लोगो की बात अनसुना कर रामू काका की मदद करने लगा। लेकिन फिर वह कई सालों के लिए गायब हो गया। रामू काका ने न जाने उसकी क्या मदद की थी कि वह फिर कुछ सालों के बाद आया और उसी तरह उनकी मदद करने लगा। उसकी मदद किसी इंसानियत से कम नहीं थी। रामू काका उसका साथ की तरह हो चुके थे जो उस आदमी को अपना घनश्याम मानने लगे। वह कई सालों में एक बार आकर दो-तीन महीने मदद करता और फिर गायब हो जाता। वैसे जानते हैं वह आदमी कौन था और कोई नहीं वही जो हर पाँच साल में नेता बनकर आता है।

न्यायालय व राजस्व ऑफिसों के दलालों की अब खैर नहीं



लेखक : किशन भावनानी

वैश्विक स्तरपर तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पारदर्शिता तेजी से बढ़ रही है महीनों का काम मिनटों से लेकर सेकंडों में हो रहा है। एक क्लिक से हजारों करोड़ रुपए गरीबों, किसानों, वंचितों के खतों में सीधे जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इसे जीरो टॉलेंस तक पहुंचाया जा सके परंतु बड़े बुजुर्गों की कहानों सच है कि नियम बनते ही तोड़ने के लिए हैं और कानून में भी अनेक लीकेजेज होते हैं जिसका फायदा जानकार लोग उठा ही लेते हैं, परंतु सरकार भी इन लिकेजेस पर संज्ञान लेकर कानूनों में संशोधन कर उसे बंद करने का प्रयास करती है, इस प्रकार का संज्ञान कानून व्यवसाई अधिनियम के तहत आने वाले सभी पहलू पहले से ही अधिवक्ता अधिनियम 1961 में शामिल है परंतु न्यायालय क्षेत्र में भी दलालों की बढ़ती दस्तक, कार्यरक्षा, हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, राजस्व अधिकारी जैसे एक्सईओ तहसीलदार पटवारी सहित सभी निचले स्तर तक कार्यालयों ने अपने परिसर में कार्य करने वाले ज्ञात दलालों की सूची बनाकर उनका वहां प्रसारण कर प्रवेश प्रतिबंधित कर सके और इस परिसर में दिखने पर 3 माह की सजा या 500 रुपए जुमाना या दोनों के रूप में सजा के पात्र होंगे। आज हम करीब करीब हर शासकीय कार्यालय में देखते हैं कि

यह मेरी नजरों के सामने होते ही रहता है। या यूं कहें कि अधिकतम नागरिक इस चैनल से पीड़ित हैं जिसकी मुख्य कड़ी दलाल

ही होता है। परंतु मेरा मानना है कि चूँकि इस संशोधित

कानून ने दलालों की सूची जो कि उसे उन अधिकारियों

के द्वारा ही बनाई जाएगी जो चैनल में शामिल हैं, तो फिर

इस संशोधन का कोई मूल्य नहीं रहेगा? क्योंकि जैसा

कि मैं देखता हूं अधिकारियों की लिक दलालों से अंदर

खाने होती ही है, उसके इशारे फोन या कोडवर्ड से ही वह

अधिकारी काम कर देता है फिर उसका पार्सल

उसे साप्ताहिक मासिक मिल जाता है।

नीचे से लेकर ऊपर तक दलालों का ही बोलबाला है और करीब करीब हरएक छोटे से लेकर बड़ा काम भी हर शासकीय कार्यालय में दलालों के हस्ते ही शीघ्रता से होता है बस!! मोटी रकम लगती है जो कि पूरी चैनल की बटोरी है यह मेरी नजरों के सामने होते ही रहता है। या यूं कहें कि अधिकतम नागरिक इस चैनल से पीड़ित हैं जिसकी मुख्य कड़ी दलाल ही होता है। परंतु मेरा मानना है कि चूँकि इस संशोधित कानून ने दलालों की सूची जो कि उसे उन अधिकारियों के द्वारा ही बनाई जाएगी जो चैनल में शामिल हैं, तो फिर इस संशोधन का कोई मूल्य नहीं रहेगा? क्योंकि जैसा कि मैं देखता हूं अधिकारियों की लिक दलालों से अंदर खाने होती ही है, उसके इशारे फोन या कोडवर्ड से ही वह अधिकारी काम कर देता है फिर उसका पार्सल उसे साप्ताहिक मासिक मिल जाता है। यह तस्वीर हर उस व्यक्ति को मालूम होगी जो इन शासकीय कार्यालयों में अपना काम कराने जाता है याने पटवारी से लेकर उच्चस्तर तक होता है इसका अंदाजा उनकी लाइफस्टाइल से ही लगाया जा सकता है कि अंदर खाने कैसी मलाई के वारे न्यारे होते हैं। बस! अब जरूरत है हर अधिकारी द्वारा अपनी अंततत्वा की आवाज सुनकर पूर्ण ईमानदारी के साथ दलालों की सूची बनाकर परिसर में प्रकाशित करें और दलालों को 3 माह की सजा दिलाने का लक्ष्य रखें! तभी इस संशोधित कानून की सार्थकता

सिद्ध होगी। चूँकि यह बिल राज्यसभा में दिनांक 3 अगस्त 2023 को पारित हो चुका है, और आज दिनांक 4 दिसंबर 2023 को संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन ही लोकसभा में पारित हो गया है अब यह दस्तखत के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा फिर कानून बन जाएगा इसीलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस ऑर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 संसद के दोनों सदनों में पारित साथियों बात अगर हम 4 दिसंबर 2023 से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में इस विधेयक के लोकसभा पारित होने की करें तो संसद ने सोमवार को अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का मकसद अदालत परिसरों में दलालों की भूमिका को खत्म करना है। लोकसभा ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा और कानून मंत्री के जवाब के बाद ध्वनिमत से स्वीकृति दी। राज्यसभा में यह विधेयक पिछले मानसून सत्र में पारित किया गया था। लोकसभा में सोमवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने अदालतों को दलालों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत बताई। बड़ी पार्टी जहां इस संबंध में बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आवश्यक प्रावधान करने पर जोर दिया। वहीं, सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि पीएम की सरकार में न्यायपालिका को स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है। हालांकि अनेक दलों ने इस

विधेयक को वापस लिए जाने और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। बड़ी पार्टी संसद ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि छोटी अदालतों में छोटे-मोटे दलालों के खिलाफ पहल करने के साथ-साथ केंद्र को बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए प्रावधान करना चाहिए।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू हुई और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता के अधीन, सत्र शुक्रवार, 22 दिसंबर 2023 को समाप्त हो सकता है। 19 दिनों की अवधि में सत्र में 15 बैठकें होंगी। साथियों बात अगर हम अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 की करें तो यह एक नया खंड,धारा 45 ए पेश करता है। 19 दिनों की अवधि में सत्र में 15 बैठकें होंगी। साथियों बात अगर हम अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 की करें तो यह एक नया खंड,धारा 45 ए पेश करता है, जिसका शीर्षक है दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने की शक्ति। विधेयक दलाल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो पारिश्रमिक के विचार से, एक कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करता है या किसी कानूनी व्यवसायी या किसी कानूनी व्यवसाय में इच्छुक पार्टी को ऐसे रोजगार का प्रस्ताव देता है। यह उन व्यक्तियों को भी संदर्भित करता है जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अदालत परिसरों, राजस्व कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आते-जाते हैं।

तेजी से बढ़ रहा है राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व , घबराहट में क्षेत्रीय दल



लेखक :अशोक भाटिया

पांच राज्यों के चुनाव में देखने लायक सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं ने क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देना उचित समझा। हालिया रिजल्ट देख कर क्षेत्रीय दलों में घबराहट है और खास कर उन दलों में जो एक विशेष जाति या समुदाय के भरोसे राजनीति करते हैं। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य में जिस हिस्सा से भाजपा और कांग्रेस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसे छोटी पार्टियों के लिए खतरों की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव छोटी पार्टियों के लिए अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। कभी यही छोटे दल केंद्र और राज्य में किंगमेकर की भूमिका निभाते थे, लेकिन आज इनका दबदबा अपने ही क्षेत्र कम होता जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही छोटी पार्टियां का दखल केंद्र और राज्यों से धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हाई है, वहां पर तो छोटी पार्टियों का वजूद भी खतरे में है। कर्नाटक और अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दल का सफ़ाया कांग्रेस ने कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी क्षेत्रीय दलों का पूरी तरह

से मतदाताओं ने इमोर कर दिया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी का खता नहीं खला तो मध्य प्रदेश में सपा, आम आदमी पार्टी सहित बसपा खाता नहीं खोल सकी। इसी तरह राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टियों का सियासी हथ्र रहा। मध्यप्रदेश में आप को 0 .54 फीसदी ,बीएसपी को 0.02 और समाजवादी पार्टी को 0.46 फीसदी वोट मिले । छत्तीसगढ़ में आप को 0.9३ फीसदी ,बीएसपी को २ .05 फीसदी वोट मिले ।राजस्थान में हालाँकि इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 और भारत आदिवासी पार्टी ने ३ सीटें जीती । बीएसपी को २ सीटें मिली ।लेकिन यहाँ भी मुख्य मुकाबला 2 राष्ट्रीय दलों के बीच रहा । ध्यान देने योग्य यह बात है कि मध्यप्रदेश में आप पार्टी ने 70 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किने थे और समाजवादी पार्टी वहां 46 सीटों पर लड़ी थी । कहा जा रहा है कि करीबी लड़ाई वाली कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने हर जीत से ज्यादा वोट पाए । बीएसपी,समाजवादी और आप पार्टी जैसे दलों के चुनाव मैदान में उतरने से जिस जाति के मतदाताओं के दम पर ये चुनाव लड़ रहे थे उनके वोट बिखर गए और उसका सीधा फायदा भाजपा को मिला । अब बात करें तेलंगाना की कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपने दो राज्यों की

सत्ता गंवानी पड़ी है, लेकिन तेलंगाना की सियासी बाजी अपने नाम कर ली है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस 119 सीटें में से 64 सीटें जीकर दक्षिण भारत के एक और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। तेलंगाना में मिली कांग्रेस की जीत और बीआरएस की हार का सियासी प्रभाव सिर्फ दक्षिण की सियासत तक ही सीमित नहीं बल्कि क्षेत्रीय की राजनीति पर भी पड़ेगा। तेलंगाना में बीआरएस को असदुद्दीन ओवैसी का साथ भी नहीं बचा सका और केसीआर सत्ता की हैटिक लगाने से चूक गए। ओवैसी भले ही सात सीटें अपनी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन केसीआर की सत्ता नहीं बचा पाए। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना के नतीजे बताते हैं कि मुसलमानों का भरपूर पकड़ पकड़ने से उठ रहा है और कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे सोचने वाली बात यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत क्या अखिलेश यादव के लिए बुरी खबर है? देखा जाय तो मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न तेजी से बदल रहा है। पहले दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मुसमलानों ने आम आदमी पार्टी से मुंह मोड़ा और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। मुसलमान यह बात अच्छे से जानते हुए कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है और कांग्रेस चुनावी लड़ाई

में नहीं है। मुस्लिमों का कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करना सियासी बदलाव के तौर पर देखा गया। दिल्ली के बाद कर्नाटक के चुनाव में मुसमलानों ने एकमुश्त वोट कांग्रेस के पक्ष में किया और जेडीएस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। जेडीएस ने 23 मुस्लिम कैडिडेट उतारे थे, लेकिन मुस्लिम इन सीटों पर कांग्रेस के हिंदू कैडिडेट के पक्ष में वोटिंग किया था। एचडी देवगौड़ा के मजबूत गढ़ पुराने मैसूर क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं को जेडीएस का करों वोटबैंक माना जाता था, जहां पर 14 फीसदी मुस्लिम हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता जेडीएस को दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एकजुट हो गए थे। वहीं, अब मुस्लिमों ने तेलंगाना चुनाव में ओवैसी की पार्टी को पुराने हैदराबाद के इलाके की सीटों पर वोट किया, लेकिन तेलंगाना के बाकी इलाके में कांग्रेस के साथ रहे। देश भर के मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का गुह राज्य तेलंगाना है। ओवैसी ने तेलंगाना में केसीआर का खुलकर समर्थन किया था। मुस्लिमों ने हैदराबाद में उनकी परंपरागत सात सीटों पर भरोसा जताया, लेकिन नरसी हिस्से में उनका जादू मुस्लिमों पर नहीं चला। ओवैसी के सहारे मुस्लिम वोटों की पूरी तरह से मिलने की आस अधूरी रह गई है।

राजस्थान में नेताओं की आपसी कलह विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को ले डूबी



लेखक :रमेश सर्पाक धमोरा

राजस्थान विधानसभा चुनाव में लोगों को जैसी अपेक्षा थी उसी के अनुरूप चुनाव परिणाम देखने को मिले हैं। पिछले पांच विधानसभा चुनाव से प्रदेश में हर बार राज बदलने की परंपरा छठी बार भी कायम रही है। अशोक गहलोत के लाख प्रयासों के उपरांत भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हर बार सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई और सत्ता गंवा दी। राजस्थान के मतदाताओं ने भाजपा की भारी बहुमत से ताजपोश कर दिए हैं ताकि अगले पांच साल तक वह बिना किसी बाधा के राज कर सके। प्रदेश में भाजपा 115 सीटों के पचास बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 108 से घटकर 69 सीटों पर ही सिमट गया है। प्रदेश के मतदाताओं ने तीसरे मोर्चे के नाम पर नेतागिर कर रहे बड़बोले नेताओं को भी चुनाव में उनकी जगह दिखा दी है। बहुजन समाज पार्टी मात्र दो सीटों पर सिमट गई। वहीं सत्ता की चाबी अपने हाथ में होने का दावा करने वाले नागौर के सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल अपनी

उन्हीं दोनों विधायकों ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन किया था। आठ निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। जिनमें से एक कांग्रेस का व सात भाजपा के बागी थे। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। मगर कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के चलते मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को सिर से ठुकरा दिया। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पार्टी के मुख्य चेहरे बने हुए थे।

खुद की खींसकर विधानसभा सीट पर मात्र 2059 मतों के अंतर से जीत सके हैं। उनकी पार्टी के सभी प्रत्याशी पराजित हो गए। चुनाव से कुछ महीना पहले ही बांगड़ के आदिवासी क्षेत्र में बनाई गई भारतीय आदिवासी पार्टी के तीन विधायक जीतने में सफल रहे हैं। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी आदिवासी क्षेत्र में पहले भारतीय ट्राईबल पार्टी के नाम से पिछले विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उसके दो विधायक जीते थे। उन्हीं दोनों विधायकों ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन किया था। आठ निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। जिनमें से एक कांग्रेस का व सात भाजपा के बागी थे। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। मगर कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के चलते मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को सिर से ठुकरा दिया। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पार्टी के मुख्य चेहरे बने हुए थे। उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। पार्टी की

सभी प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर और होर्डिंगों में अशोक गहलोत ही छाप हुए थे। अशोक गहलोत द्वारा हायर की गई प्रचार कंपनी डिजाइन बॉक्स व उसके बड़बोले निदेशक नरेश अरोड़ा भी चुनाव जितवाने में नाकाम रहे। सचिन पायलट पूरे चुनाव में ही साइड लाइन रहे। टिकट वितरण के दौरान सचिन पायलट ने जिस तरह से गहलोत के सामने हथियार डाले दिये थे। उस पर बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी आश्चर्य हुआ था। चुनाव से पहले शुचिता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले पायलट ने जिस तरह से गहलोत समर्थक शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया जैसे विवादित लोगों को टिकट देने पर अपनी सहमति जताई उससे सभी अर्चभित रह गए। लोगों का कहना था कि पायलट ने अपने समर्थक कुछ लोगों के टिकट क्लीयर करवाने के चक्कर में गहलोत से अंदर खाने अछोषित समझौता कर लिया था। चुनाव में पायलट के कहने पर करीबन 40 लोगों को टिकट मिली जबकि गहलोत समर्थकों की संख्या 150 से भी ऊपर थी। चुनाव



से पहले गहलोत बार-बार कहते थे कि प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल नहीं है। जनता प्रदेश सरकार के कामों से खुश है। विधायकों को लेकर जनता में नाराजगी है। इसलिए हम बड़ी संख्या में नए लोगों को मैदान में उतारेंगे। मगर चुनाव आते-आते सारी बातें कागजों में ही रह गई और धड़ाधड़ बूढ़े व मौजूदा विधायकों को मैदान में उतार दिया गया। जिसका नतीजा कांग्रेस को करारी हार के रूप में देखना पड़ा। अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुद को चेहरा बना कर कर दी। राजस्थान में भाजपा ने किसी को भी चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा था। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे व कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ा था। वहीं अशोक गहलोत ने सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर खुद को ही आगे कर पूरी चुनावी व्यूह रचना की थी जिसमें वह नाकाम रहे। कई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को अपने बागी प्रत्याशियों की नाराजगी के चलते भी हार का सामना करना पड़ा है।

यदि आप आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीखमिस कर चुके हैं तो भी निश्चित रहिए

- आयकर कानून के मुताबिक, आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

परिवहन विशेष न्यूज

यदि आप आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख मिस कर चुके हैं तो भी निश्चित रहिए, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बाद भी जुमाना नहीं भरना पड़ेगा। दरअसल, इस वर्ष आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी, जो बीत चुकी है। इसलिए ऐसे लोग जो समय पर आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस कर चुके हैं, तो उन्हें बिलेटेड आईटीआर फाइल करते समय निर्धारित जुमानों का भुगतान करना पड़ेगा।

हालांकि, कुछ ऐसे 'भाग्यशाली' व्यक्ति हैं जो आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद



भी जुमानां दिए बिना ही अपना आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल कर सकेंगे। क्योंकि इनके लिए आयकर रिटर्न भरने में देरी होने पर भी जुमानों में छूट का प्रावधान तय है। बस यह बात उन्हें समझनी जरूरी है।

तो आइए एक नजर डालते हैं कि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा से चूकने पर किन-किन लोगों को जुमानों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आयकर कानून के मुताबिक, आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद

आईटीआर दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है और वह देर से आईटीआर दाखिल करता है, तो वह विलम्ब से आईटीआर दाखिल करने के लिए जुमानां भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

समझिए, आयकर की धारा 234एफ के तहत विलम्ब से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी मिलती है छूट

आयकर विभाग ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया है कि, 'यदि सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होती है तो समयसीमा के बाद दाखिल किए गए आईटीआर पर धारा 234एफ के तहत उल्लिखित विलंब शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, 'धारा 139(1) में उल्लिखित सकल कुल आय का मतलब अधिनियम के तहत धारा 80सी से 80यू के तहत कटौती को ध्यान में रखने से पहले कुल आय से होती है।

जानिए, किसी व्यक्ति पर लागू मूल कर छूट उसके द्वारा चुनी गईं कर व्यवस्था पर करती है निर्भर, इसलिए बराबरी पूरी सावधानी

मौजूदा कर कानूनों के मुताबिक, किसी व्यक्ति पर लागू मूल कर छूट सीमा उसकी ओर से चुनी गईं कर व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये होगी, भले ही उसकी उम्रसीमा कुछ भी हो। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मूल छूट सीमा व्यक्ति

की उम्र पर निर्भर करती है।

वर्तमान में, 60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है। वहीं, 60 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 3 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट दी गई है।

वहीं, अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु के) के लिए, मूल छूट सीमा 5 लाख रुपये तक है।

यहां पर यह स्पष्ट कर दें कि बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब की घोषणा की है।

हालांकि, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत नए आयकर स्लैब चालू वित्त वर्ष 2023-24 (यानी 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच) और वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए अगले साल आईटीआर दाखिल करते समय अर्जित आय के लिए लागू होंगे। विलम्ब से आईटीआर दाखिल करने

से सम्बंधित उपरोक्त नियम के ये हैं अपवाद

यद्यपि, उपरोक्त नियम के दो अपवाद हैं- पहला अपवाद व्यक्तियों के कुछ समूहों/वर्गों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही उनकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक न हो।

जानकारों के मुताबिक, 'अगर कोई व्यक्ति धारा 139 (1) के सातवें नियम में उल्लिखित किसी भी शर्त को पूरा करता है, तो उसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा।

यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर धारा 234 एफ के तहत शुल्क लगाया जाएगा।

जानिए, धारा 139 (1) के सातवें नियम के तहत तीन तीन व्यक्ति आते हैं-

पहला, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने बैंक या सहकारी बैंक के एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल

राशि जमा की है।

दूसरा, जिन्होंने किसी विदेशी यात्रा के लिए अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।

तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिजली की खपत के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।

ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त में से किसी भी एक कारण के अंतर्गत आते हैं।

ऐसे में यदि आप ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त के अंतर्गत आते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने समय सीमा से पहले अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर लिया है,

अन्यथा आपको विलंब शुल्क भरना पड़ेगा, भले ही आपकी सकल कुल आय कर योग्य सीमा से नीचे हो।

- जैसे कि विदेशी कंपनी के स्टॉक इत्यादि और उस विदेशी संपत्ति से आपको आमदनी होती है तो आपको हर हाल में समय से पहले आईटीआर दाखिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर आपको जुमानां भरना पड़ेगा

समझिए, विदेशी संपत्ति से आमदनी होने पर भी भरना पड़ेगा जुमानां

दूसरा अपवाद यह है कि यदि आप विदेशी संपत्ति रखते हैं जैसे कि विदेशी कंपनी के स्टॉक इत्यादि और उस विदेशी संपत्ति से आपको आमदनी होती है तो आपको हर हाल में समय से पहले आईटीआर दाखिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर आपको जुमानां भरना पड़ेगा, फिर चाहे आपकी आमदनी कुल आय कर योग्य सीमा से कम ही क्यों ना हो।

इसलिए बेहतर यही होगा कि आप आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख कदापि मिस नहीं करें, अन्यथा अपने अनुकूल नियमों की पूरी जानकारी रखें

संक्षिप्त खबरें

सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी ला रही है आईपीओ, सेबी में जमा किए ड्राफ्ट पेपर

सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी अल्टेक्स सोलर जवद शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। कंपनी ने सेबी में ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। कंपनी एनएसई उभरना में लिस्ट होगी। अल्टेक्स सोलन ने बयान जारी कर बताया कि वह कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटा रही है। अल्टेक्स सोलर के आईपीओ का इश्यू साइज 6480000 इक्विटी शेयरों का होगा।

अल्टेक्स सोलर के आईपीओ का इश्यू साइज 64,80,000 इक्विटी शेयरों का होगा।

अल्टेक्स सोलर ने एलाब किया है कि वहशुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाने वाली है। कंपनी केपैसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाना चाहती है। एपेक्स सोलर ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने एनएसई उभरना में लिस्टिंग के लिए ड्राफ्ट पेपर सबमिट किए हैं।

कंपनी ने फिलहाल यह जानकारी नहीं दी है कि वह आईपीओ के जरिए कितनी राशि जुटाना चाहती है। अपने बयान में यह जरूर कहा कि वह अपनी शुद्ध आय के 19.55 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी क्षमता को 750 मेगावाट तक अपग्रेड और एक्सपेंड करना चाहती है।

इसके साथ ही कंपनी 12.94 करोड़ रुपये की लागत से सोलर मॉड्यूल का एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी को सामान्य कॉर्पोरेट खर्च और वॉकिंग कैपिटल रियायतमेंट के लिए 20.49 करोड़ रुपये की जरूरत है।

अल्टेक्स सोलर इश्यू साइज समाचार एजेंसी पीटीआईके के मुताबिक, इस आईपीओ के इश्यू साइज 10 रुपये प्रति मूल्य वाले 64,80,000 इक्विटी शेयरों का होगा। इसके के लिए कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है, जबकि कार्गिलाइब फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इश्यू का रजिस्ट्रार है।

एल्टेक्स सोलर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अश्वनी सहगल ने कहा, बाजार की मांग को पूरा करने के लिए हमें बड़े-साइज के सेल, लीड-बस बार्स (एमबीबी) और लेटेस्ट प्रकार के मोनो पर्व, टॉपकॉन और बायफेसियल सेल के लिए हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए बाजार से फंड जुटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम अपनी मौजूदा मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की क्षमता 450 मेगावाट से बढ़ाकर 1.2 गीगावॉट तक करना चाहते हैं। अश्वनी सहगल ने कहा, कंपनी एल्यूमीनियम फ्रेम के प्रोडक्शन के डेडिकेटेड प्लांट बनाने पर भी विचार कर रही है, जिससे अन्य देशों से फ्रेम के आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी।

अल्टेक्स सोलर क्या करती है ? ग्रेटर नोएडा स्थित कंपनी बी2बी मार्केट में सोलर पैनलों की मैन्यूफैक्चरिंग और डिलीवरी करती है। यह एल्यूमिनस, जैक्सन, और टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। अल्टेक्स सोलर ने वित्त वर्ष 2013 में 183.93 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया, जो वित्त वर्ष 2012 में 156.06 करोड़ रुपये था। वहां बात करे चालू वित्त वर्ष की तो अप्रैल-सितंबर अवधि में कंपनी 207.13 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

परिवहन विशेष न्यूज

विधानसभा चुनावों के नतीजे ने के बाद शेयर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर तेजी से काम कर रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार में निफ्टी ने ऐतिहासिक ओपनिंग की है। निफ्टी को इस दिन 450 अंकों से अधिक की ओपनिंग मिली है। इस शानदार ओपनिंग के बाद निफ्टी टॉप गेनर की सूची में शामिल हो गया है। वहीं अडानी के साथ बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, एमएडएम के शेयर भी उछल मार रहे है। मंगलवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में घरेलू बाजारों में तेजी देखने को मिली है। ऐसी रही शेयर बाजार की ओपनिंग शेयर बाजार की ओपनिंग की बात



की जाए तो मंगलवार को सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स ने शानदार ओपनिंग की है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ना सिर्फ जीत हासिल करने वाली पार्टियों में खुशी है बल्कि शेयर बाजार में भी इस जीत का खुमार छाया हुआ है। नतीजे आने के बाद दूसरे दिन भी जीत का असर बाजार पर दिख रहा है। मंगलवार पांच दिसंबर को भी निफ्टी और

सेंसेक्स रिकॉर्ड उंचाई पर बंद हुए है। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 169.94 अंक उछलकर 69,035.06 के नए शिखर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 52.60 अंक चढ़कर 20,739.40 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स की कंपनियों में अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी पोर्ट्स ने अपनी बढ़त बरकरार

आईटीआर सम्बन्धी नोटिस का जवाब नहीं देने वालों की जांच करेगा आयकर विभाग

- इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जहां अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न यानी आईटीआर नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएससी) को भेजा जाएगा

परिवहन विशेष न्यूज

आयकर विभाग ने जांच' के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में कतिपय दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत ऐसे करदाताओं, जिन्होंने आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। आय कर विभाग उन मामलों की जांच भी करेगा



जहां किसी लॉ इंफोसमेंट एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टैक्स चोरी से संबंधित विवेचन जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, आयकर अधिकारियों को आय में गड़बड़ी के बारे में करदाताओं को प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना

होगा। जिसके बाद करदाताओं को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जहां अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न यानी आईटीआर नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएससी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं आयकर विभाग ऐसे

मामलों की सूची जारी करेगा, जिनमें सक्षम प्राधिकरण की छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है। जीएसटी की चोरी करने वालों की बढ़ती मुश्किलें

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड' (सीबीआईसी) ने 2019-20 और उसके बाद जीएसटी रिटर्न की स्कूटनी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिअर्स (एसओपी) जारी किया है। इनका इस्तेमाल जीएसटी की एनालिटिक्स यूनिट की ओर से विभिन्न प्रकार के जोखिम के आधार पर जीएसटी रिटर्न की स्कूटनी करने के लिए होगा। बताया जाता है कि स्कूटनी के लिए जीएसटी रिटर्न' का चयन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिक्रू मैनेजमेंट करेगा। चुने जीएसटीआईएन से

जुड़ी सभी जानकारी उससे जुड़े केंद्रीय कर अधिकारी के स्कूटनी बोर्ड पर दिखेगी। जोखिम मापदंडों की गणना के लिए डैशबोर्ड' पर उपलब्ध डाटा को एक विशेष पाईट के समय पर उत्पन्न किया गया है, इसलिए इसमें रिटर्न की जांच के समय बदलाव हो सकता है।

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 142(1) आयकर अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है। हालांकि आयकर अधिकारियों को आय में गड़बड़ी के बारे में करदाताओं को प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 जून तक नोटिस भेजना होगा। मसलन, जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी सहित पेश करने को कहा

जाता है। ऐसे मामलों में आयकर विभाग एक इंटीग्रेटेड लिस्ट जारी करेगा, जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रियायत या कटौती की मांग करता है।

इसके अलावा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत टैक्सपेयर्स को एनएफएससी के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा।

इससे स्पष्ट है कि आयकर विभाग अब नई जांच शुरू कर चुका है। इसके तहत ऐसे आयकरदाताओं की अनिवार्य जांच की जाएगी, जिन्होंने विभाग के भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है।

वहीं उन मामलों की भी जांच होगी, जहां कर चोरी के संबंध में विशद जानकारी किसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों या नियामक प्राधिकरणों

- इस बारे में आयकर विभाग ने स्पष्ट कहा है कि कर अधिकारियों को आय में गड़बड़ियों के बारे में आयकरदाताओं को प्रत्येक वित्त वर्ष के 30 जून तक नोटिस भेजना होगा।

ने दी है। इस बारे में आयकर विभाग ने स्पष्ट कहा है कि कर अधिकारियों को आग में गड़बड़ियों के बारे में आयकरदाताओं को प्रत्येक वित्त वर्ष के 30 जून तक नोटिस भेजना होगा। इसके बाद आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे। अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है तो ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएससी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा।

बैंक एफडी में किसी प्रकार के नुकसान से

ख़ाताने के लिए जोखिमों के खारे में अवश्य जानें

परिवहन विशेष न्यूज

सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लोगों को निश्चित रिटर्न मिलता है बल्कि जोखिम भी कम रहता है। लेकिन, वास्तव में ऐसा नहीं है। एफडी को खले ही सबसे कम जोखिम वाला निवेश विकल्प माना जाता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जहां इसमें बैंकों के डिफॉल्ट करने पर आपका पैसा दुबने का खतरा रहता है। वहीं मैच्योरिटी से पहले फंड निकाली की सुविधा नहीं होती है। खास बात यह कि महंगाई भी एफडी के ब्याज को प्रभावित करती है।



फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) हमेशा से ही निवेश का लोकप्रिय साधन रहा है। क्योंकि इसमें निवेशकों को न सिर्फ निश्चित रिटर्न मिलता है बल्कि जोखिम भी कम रहता है। लेकिन, वास्तव में ऐसा नहीं है। एफडी को खले ही सबसे कम जोखिम वाला निवेश विकल्प माना जाता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जहां इसमें बैंकों के डिफॉल्ट करने पर आपका पैसा दुबने का खतरा रहता है। वहीं मैच्योरिटी से पहले फंड निकाली की सुविधा नहीं होती है। खास बात यह कि महंगाई भी एफडी के ब्याज को प्रभावित करती है।

लिहाजा, यहां पर हम अपने पेशेवर

अनुभव के आधार पर ऐसे ही पांच जोखिम के बारे में बता रहे हैं, जिनका एफडी कराते समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

पहला, हमेशा बना रहता है डिफॉल्ट का ख़ाता

आमतौर पर कई बार बैंक दुबने जैसी परिस्थिति/सिचुएशन देखी गई है। ऐसे में निवेशक/इंवेस्टर की जमा पर खतरा बढ़ जाता है। बहरहाल, आरबीआई के नए नियम के तहत किसी बैंक के दुबने पर कुल जमा पर महज 5 लाख रुपये तक का ही इश्योरेंस मिलता है। लिहाजा, यदि किसी बैंक में 15 लाख रुपये का एफडी किया हुआ है और वह

बैंक डूब जाता है तो आपको केवल 5 लाख रुपये तक ही मिलेंगे। बाकी 10 लाख रुपये के दुबने का खतरा रहता है। कुछ स्पॉल को-ऑपरेटिव बैंक के दुबने के मामले भी सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में निवेशकों की जमा पर जोखिम बढ़ जाता है।

दूसरा, मैच्योरिटी से पहले फंड निकाली नहीं और यदि की तो ग़रबी पड़ती है पेनेल्टी, कोई ब्याज भी नहीं मिलता

कोई भी सावधि जमा (एफडी) में एक निश्चित अवधि के लिए ही निवेश किया जाता है। लिहाजा, इसमें तय अवधि से पहले आप अपने फंड की निकासी नहीं कर सकते हैं। वहीं, मान लीजिए कि आपने टैक्स सविंग एफडी किया है, जिसकी लॉकअप अवधि पांच साल है तो आप मैच्योरिटी के बाद ही फंड की निकासी कर सकते हैं। जबकि मैच्योरिटी से पहले फंड की निकासी पर आपको नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कई बैंक एफडी से ऑनलाइन निकासी की सुविधा नहीं देते हैं। ऐसे में फंड निकासी के लिए आपको बैंक शाखा जाकर कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप जरूरत पर पैसा निकालना चाहते है तो एफडी तोड़ी नहीं जा सकती।

लेकिन फिर भी यदि आप उसे तोड़ते हैं तो बैंक आपको ब्याज नहीं देगी और पेनेल्टी भी भरनी होती है, सो अलग। हां, पेनेल्टी कितनी हो सकती है ये एफडी करते समय शर्तों में लिखा होता है, जो हर बैंक की अलग-अलग हो सकती है। तीसरा, 60 साल से कम उम्र के लोगों को क़रना पड़ता है अधिक टैक्स का भुगतान

फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज से होने वाली कमाई करयोग्य (टैक्सबल) होती है। इस पर कमाई के साथ जोड़कर स्लेब के हिसाब से टैक्स लगता है। हालांकि, यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आपको आयकर कानून की धारा 80 बी के तहत एफडी पर ब्याज के रूप में होने वाली कमाई पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है।

यद्युर्थ, महंगाई बढ़ने पर होता है कम गुनापा

आपको पता है कि कमरतोड़ महंगाई, हर प्रकार के निवेश को प्रभावित करती है। साथ ही निवेश जोखिम भी बढ़ाती है।

मान लीजिए, कोई बैंक एफडी पर 8 फीसदी ब्याज दे रहा है और उस समय महंगाई की दर 7 फीसदी है तो आपको

अपनी जमा धनराशि पर वास्तविक रिटर्न सिर्फ एक फीसदी ही मिल रहा है। हां, इतना जरूर है कि एफडी पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन, वास्तविक रिटर्न महंगाई के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। जिससे कम मुनाफा होता है। इसमें बाजार में होने वाले मुनाफे का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें इंटरस्ट रेट फिक्स रहती है। वहीं, अगर महंगाई दर 6 फीसदी हो गई और आपको मिलने वाला ब्याज केवल 5 से 6 फीसदी है तो ऐसे में आपको केवल नेगेटिव रिटर्न ही मिलेगा।

इसलिए एफडी करने से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकीपूर्वक विचार कर लीजिये। अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं।

पांचवां, फ़िर से निवेश पर क़म ब्याज

सावधि जमा (एफडी) मैच्योर होने पर आपके पास दो विकल्प ही बचे होते हैं। पहला, आप पैसे निकाल लें। दूसरा, एफडी के रूप में फिर से निवेश कर दें। आप चाहें तो नई एफडी भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इस पर उतना ही ब्याज मिलेगा, जो अभी लागू है। स्वाभाविक है कि इस कदम से आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर जोखिम बढ़ जाएगा,

क्योंकि इस एफडी पर पहले की तरह आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। इससे स्वाभाविक है कि रिटर्न कम मिलता है। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का पहला नुकसान ये है कि इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। यानी जो ब्याज आपको बैंक ने दिया है, वो फिक्स रहता है।

जबकि स्टॉक या म्यूचुअल फंड जैसे बाकी इन्वेसमेंट ऑप्शन में आपको जो ब्याज मिलता है, वो एफडी से कहीं ज्यादा होता है। निष्कर्षतः निवेश सलाहकार बताते हैं कि एफडी कराते समय मर्यादा, डिफॉल्ट, रिटर्न, टैक्स देनदारी की गणना अवश्य करें। वहीं, अपनी पूरी रकम कभी भी एफडी में न डालें। बल्कि ऐसे सधनों में भी निवेश करें, जहां से जरूरत पड़ने पर आपको पूंजी मिल जाए। इसलिए एक इन्वेस्टर को इसके बारे में समझने और जानने की जरूरत होती है।

आइए एफडी में होने वाले नुकसान के लिए आप जीवन भर खुद को कोसते रह जायेंगे। क्योंकि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में जरा-सी चूक से किसी की भी घाटा हो सकता है। इसलिए उर्ध्वचूक बातों का खास ध्यान रखिए, जो अक्सर बैंक आपको नहीं बताता है, जिससे आप ठगे से रह जाते हैं।

वोटिंग पैटर्न को लेकर दिग्विजय ने उठाए सवाल, कहा- जिस मशीन में चिप हो, वो हो सकती है हैक

पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद! तस्वीरों के आँकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है।

भोपाल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने 199 विधान सभा सीटों पर पोस्टल बैलेट में मिले कांग्रेस को वोट और ईवीएम में मिले कांग्रेस के वोटों का आकलन करने की बात कही है। सिंह का कहना है



वोटिंग पैटर्न में इतना बदलाव कैसे हो सकता है। जिन सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही है वहां ईवीएम में हार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पोस्ट कर ईवीएम का ये राग छेड़ा है। उन्होंने कई देशों में ईवीएम पर रोक होने का भी हवाला दिया है।

दिग्विजय सिंह पोस्ट

पोस्टल बैलेट के जरिए

कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद! तस्वीरों के आँकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है। जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता (यानी लोक)

हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। अब कुल 230 सीटों के आँकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है, सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया?

किया जा सकता है हैक

सिंह का कहना है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है।मैने 2003 से ही ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं! यह मौलिक प्रश्न है, जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। माननीय चुनाव आयोग और माननीय

सर्वोच्च न्यायालय क्या आप कृपया हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? डॉक्टर गोविंद सिंह बोले ईवीएम हैक करके बदले गए परिणाम

इधर, लहार विधानसभा से हार का मुंह देखने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किये हैं। उनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि जनता रो रही है। बीजेपी खुशियां मना रही है। एश्ट हैक करके परिणाम बदले गए हैं।

बीजेपी का काउंटर

ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी यह भी बता दीजिये कि जयवर्धन सिंह चुनाव ईवीएम की गड़बड़ी से जीते है

क्या। इतना ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना का चुनाव ईवीएम की गड़बड़ी से जीती है क्या। समझा जा सकता है कि लक्ष्मण सिंह जी, प्रियव्रत सिंह, केपी सिंह हार गये है और जयवर्धन सिंह जीत गये है, तो पारिवारिक नाराजगी दूर करने के लिये आपको ईवीएम पर दोष देना ही पड़ेगा।

ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई हैं। कांग्रेस का एक धड़ा जहां ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरा भाग इसे सिरे से नकार रहा है। दिग्विजय सिंह को अपने भाई लक्ष्मण सिंह का ही साथ इस मामले में नहीं मिला है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, मैं खुद कई बुथों पर जीता हूं। राजेंद्र भारती, नितेश राठौर, अजय सिंह जैसे कई अन्य प्रत्याशियों ने भी ईवीएम पर भरोसा जताया है।

23 दिसंबर से होगी खाए भर्ती परीक्षा, जानिए कब से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड



यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसके एडमिट कार्ड आठ दिसंबर को वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अनुमन्य नहीं होगा।

देहरादून

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जेई भर्ती परीक्षा 23 से 27 दिसंबर तक कराएगा। आयोग ने इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आठ दिसंबर को जारी किए जाएंगे। आयोग सचिव गिधारी सिंह रावत के मुताबिक, उत्तराखंड सम्मिलित

राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 व 27 दिसंबर को 14 शहरों में अलग-अलग केंद्रों पर होगा। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसके एडमिट कार्ड आठ दिसंबर को वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अनुमन्य नहीं होगा।

23 दिसंबर को पहली पाली में सामान्य हिंदी, दूसरी पाली में सामान्य अंग्रेजी, 24 दिसंबर के पहली पाली में सिविल इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्नपत्र, दूसरी पाली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रथम, दूसरी पाली में द्वितीय पेपर होगा। 27 दिसंबर को इलेक्ट्रिक, एप्लीकल्ड इंजीनियर प्रथम प्रश्नपत्र और दूसरी पाली में द्वितीय पेपर होगा।

अयोध्या के होटलों पर देश के बड़े समूहों की नजर, नौ लाख से लेकर दो करोड़ तक में कर रहे करार

अयोध्या

मंदिर का लोकार्पण होने से पहले अयोध्या के होटलों पर देश के बड़े समूहों की नजर है। मासिक और वार्षिक किराया देकर लीज पर इनका संचालन अपने हाथों में लेने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। ऐसा होने के बाद हिल स्टेशन और बड़े महानगरों की तरह उच्चस्तरीय सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह अलग बात है कि इसके लिए यहां ठहरने वाले अतिथियों को पहले की अपेक्षा अधिक रकम खर्च करनी पड़ सकती है। आने वाले समय में अयोध्या में बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटकों का आगमन होना तय है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर कई नए होटलों की स्थापना के लिए इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू भी हो चुके हैं। कुछ होटल निर्माणाधीन हैं। कई के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। इस बीच कुछ बड़े समूहों ने एक नया रास्ता तलाश लिया है। होटल निर्माण की लंबी और जटिल



प्रक्रिया से बचने के लिए वो यहां पर पहले से संचालित होटलों को लीज पर ले रहे हैं। हाल ही में दिल्ली, गुड़गांव, वाराणसी और लखनऊ के कुछ होटल समूहों ने यहां के होटलों को लीज पर लेकर उनका संचालन अपने मानकों के अनुरूप करना शुरू भी कर दिया है। इसके एवज में वह स्थानीय मालिकों को नौ लाख रुपये महीने से लेकर दो करोड़ रुपये वार्षिक तक देने का करार कर चुके हैं। इनमें कलाक, कामाय, सीजनेट और आर्यन जैसे समूहों का नाम सामने आया है। अपना होटल लीज पर देने के बाद स्थानीय मालिक को कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। सब कुछ उस समूह के हाथ में रहेगा जो इन्हें लीज पर लेगा।

प्रोफेशनल, बहुभाषी और प्रशिक्षित स्टाफ रखेंगे कोहिनूर पैलेस होटल के संचालन का जिम्मा कामाय समूह को देने वाले विनय पटेल ने बताया कि आने वाले समय में यहां पर होटल इंडस्ट्री के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में स्थानीय होटल संचालक टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए लीज पर देना ही बेहतर है। बड़े समूह अब यहां पर प्रोफेशनल, बहुभाषी और प्रशिक्षित स्टाफ रखेंगे। सुविधाओं के स्तर को भी उच्चतक किया जाएगा। यह सब खुद कर पाना यहां के होटल व्यवसायियों के लिए आसान नहीं है। इसीलिए अपना होटल लीज पर देने वालों की संख्या बढ़ रही है।

बारिश-बर्फबारी के बाद मौसम खुला, पर टिडरन बढ़ी; चार स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में

शिमला

हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश-बर्फबारी के बाद मंगलवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन टिडरन लगातार जारी है। राज्य में चार स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। जबकि दो स्थानों पर शून्य डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बर्फबारी के बाद राज्य के जनजातीय क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। औसत अधिकतम तापमान सामान्य भागों में भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रमुख स्थानों का न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 4.6, सुंदरनगर 4.7, भुंतर 2.1, कल्पा माइनस 1.6, धौलागंगा 8.2, ऊना 6.4, नाहन 10.1, केलांग माइनस 7.3, पालमपुर 5.2, सोलन 5.5,



11 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हो सकती है। धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में भी मौसम साफ बना हुआ है।

प्रमुख स्थानों का न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 4.6, सुंदरनगर 4.7, भुंतर 2.1, कल्पा माइनस 1.6, धौलागंगा 8.2, ऊना 6.4, नाहन 10.1, केलांग माइनस 7.3, पालमपुर 5.2, सोलन 5.5,

मनाली माइनस 0.6, कांगड़ा 7.0, मंडी 4.4, चंबा 6.1, डलहौजी 6.0, जुब्बड़हट्टी 7.6, कुफरी 2.5, नारकंडा 0.4, रिकॉगपिओ 0.9, सेरुबाग 1.8, धौलाकुआ 11.6, बरटी 7.7, समथो माइनस 2.8, पांवटा साहिब 13.0 और देहरागोपीपुर में 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ी पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों

की आमद बढ़ गई है। हाल ही में हुई बर्फबारी और बाद से क्षतिग्रस्त सड़क चकाचक होने से पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। होटलों की एडवांस बुकिंग में भी इजाफा हुआ है। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वर्ष मनाली में पर्यटन कारोबार ठीक नहीं रहा। समर सीजन में पर्यटकों की संख्या काफी कम दर्ज की गई। ग्रीन टेक्स बैरियर से मिले आंकड़ों के अनुसार मनाली में इन दिनों हर रोज लगभग 600 पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। जबकि पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 400 के करीब था।

हाट पीक पर बर्फबारी से सैलानी बढ़ने की उम्मीद वहीं, बर्फबारी के बाद नारकंडा में सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। हर साल विंटर टूरिस्ट

सीजन के दौरान हजारों की संख्या में सैलानी बर्फ में अटखेलियां करने के लिए नारकंडा पहुंचते हैं। बर्फबारी के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए होटलों में कमरों की बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जाने वाले सैलानी भी नारकंडा में एक दिन का ठहराव करते हैं। बर्फबारी के बाद स्थानीय होटल और होम स्टे संचालकों को विंटर सीजन अच्छा जाने की उम्मीद है। स्थानीय पर्यटन कारोबारी विक्रांत श्याम का कहना है कि होटलों में कमरों की बुकिंग के लिए पूछताछ पहले ही आ रही थी, अब बर्फबारी के बाद बुकिंग कंफर्म होने की उम्मीद है। साहसिक खेलों के आयोजक रणजीत डोहरा का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर भारी बर्फबारी होती है तो स्कीइंग का आनंद लेने के लिए भी नारकंडा में सैलानियों का खूब जमावड़ा लगेगा।

कांग्रेस के लिए प्रदेश में 10 वर्षों का सूखा खत्म करने की बढ़ी चुनौती

देहरादून

लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीते 10 वर्षों का सूखा खत्म करने की आस लगाए बैठी कांग्रेस का मनोबल चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से धड़ाधद हो गया है। हिंदी भाषी चार राज्यों के विस चुनाव में पटखनी खाने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकारों को कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, ताकि चुनाव से पूर्व उनके बीच नया जोश भर जा सके। राज्य में वर्ष 2022 के विस चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त थी, पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर परिणाम आने से पहले ही खींचतान शुरू हो गई थी। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही उसका यह अति उत्साह मुंह के बल गिर गया। इसके बाद पड़ोसी राज्य हिमाचल ने जीत का मरहम लगाया तो कार्यकर्ताओं में एक बार फिर उत्साह लौट आया। लेकिन इस बार दो राज्यों



राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई और दो अन्य राज्य मध्य प्रदेश और मिजोरम में करारी हार से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चार राज्यों की इस हार ने तेलंगाना की जीत को भी फीका कर दिया।

नए सिरे से संयंत्र में जुटे कल तक पांच में से करीब चार राज्यों में जीत

को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे पार्टी के नेता अब नए सिरे से संयंत्र में जुट गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीते 10 साल से प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हुए हैं। उत्तराखंड ही नहीं केंद्रीय राजनीति में मोदी के करिश्माई नेतृत्व की काट फिलहाल उसके पास दिखाई नहीं दे रही है।

इन चुनावों ने खासकर हिंदी भाषी राज्यों में मोदी का करिश्मा बरकरार रहने और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का दांव नहीं चलने वाले परिणाम दिए हैं। ऐसे में पार्टी रणनीतिकारों को एक बार फिर से व्यापक रणनीति बनाने, बेहतर बृथ प्रबंधन और अंतर्विरोध की राजनीति से उबरने का सबक लेना होगा।

इन चुनावों में मुद्दे हारे हैं, खैरात जीती है: माहरा चार राज्यों में पार्टी की करारी हार पर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस के मुद्दों की हार और भाजपा की खैरात की जीत हुई है।

उन्होंने कहा कि जनादेश हम सिर-माथे से स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में हम ज्यादा मेहनत करेंगे। हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, जिन्हें हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। हम जनता से पूछेंगे कि बीते 10 साल में आपने भाजपा को दोनों बार पांच-पांच सांसद दिए हैं, बदले में उन्होंने आपको क्या दिया है।

सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों हॉस्टल के छात्र भाग निकले। मामले में अभी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

प्रयागराज

कर्मलगंज में रात एक बजे के करीब जीएन झा और एस एस एल हॉस्टल के छात्रों के बीच पहले पथराव हुआ। फिर बमबारी हुई। सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों हॉस्टल के छात्र भाग निकले। मामले में अभी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बमबाजी

हॉस्टल के छात्र आपस में मिड़े, जमकर हुआ पथराव और बमबारी; 100 पर एफआईआर

सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों हॉस्टल के छात्र भाग निकले। मामले में अभी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।



और पथराव करने वालों की तलाश में जुट गई है। मामले में नाका चौकी प्रभावी की ओर से खुद तहरीर देकर लगभग 100 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ बलवा बमबाजी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों हॉस्टल आमने-सामने स्थित है। एसीपी राजेश यादव का कहना है

कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि दिन में छोले भट्टे की दुकान पर किसी बात को लेकर दोनों हॉस्टल के कुछ छात्रों के बीच विवाद हुआ था। रात में झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था कोई अन्य विवाद था। यह उपद्रव में शामिल लड़कों के पकड़े जाने के बाद ही बताया जा सकेगा।

निलंबन रद्द होते ही संसद पहुंचे राघव चड्ढा, केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा

नई दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मंगलवार को संसद पहुंचे। जहां उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। संसद परिसर में महात्मा गांधी के स्टेच्यू के पास आप सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीते सोमवार को पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का 115 दिनों बाद निलंबन रद्द हुआ। संसद परिसर में आप सांसद राघव चड्ढा के अलावा अन्य पार्टी के सांसद भी नजर आए। सभी के हाथों में तख्ती नजर आई। इन तख्त्वों पर लिखा 'जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो', 'मनीष सिखादिया को रिहा करो', 'संजय सिंह को रिहा करो', 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो।' आम आदमी पार्टी सिर्फ संसद ही नहीं दिल्ली में भी शराब घोटाले को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। सीएम केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का



115 दिनों के बाद सोमवार को संसद में एक प्रस्ताव लाकर उनका निलंबन रद्द कर दिया। निलंबन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा संसद पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू का जीवन हमें सिखाता है कि चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि 11 अगस्त 2023 को मुझे संसद से निलंबित कर दिया गया था। अपना निलंबन रद्द करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेरा निलंबन समाप्त हुआ है। इसके लिए सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता का धन्यवाद

किया है। इस मौके पर राघव चड्ढा ने कहा कि दोबारा सदन में जाकर देश की आम जनता की आवाज उठाएंगे। बीते 115 दिनों तक संसद के अंदर जाकर देश की आम जनता की आवाज नहीं उठा सका, जनता के हक का सवाल सरकार से नहीं पूछ सका और देश की जनता सरकार से जो जवाब चाहती थी, वो जवाब नहीं ला सका। मुझे खुशी है कि 115 दिन बाद हो सही, मेरा निलंबन आज समाप्त हो गई है। निलंबन के दौरान देश के लोगों का आशीर्वाद और दुआएं मिलीं। लोगों ने मुझे फोन, ईमेल और सदेश भेजकर मुझे बहुत प्यार, आशीर्वाद दिया, मुझे डट रहने, लड़ाई लड़ने और इन लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत दी।

गठबंधन की छह दिसंबर को होने वाली बैठक टली, ममता-नीतीश समेत कई नेताओं ने आने में जताई असमर्थता

कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, अब छह दिसंबर को शाम छह बजे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, अब छह दिसंबर को शाम छह बजे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आयोजित की जाएगी। बाद में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इस गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक में न आ पाने के चलते बैठक को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, अब छह दिसंबर को शाम छह बजे



इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आयोजित की जाएगी। बाद में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इस गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक में न आ पाने के चलते बैठक को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, अब छह दिसंबर को शाम छह बजे

करना पड़ा है। गौरतलब है कि सपा नेता अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ही इंडिया की बैठक में जाने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक के नेता एमके स्टालिन ने चक्रवात के कारण पैदा हुए हालात के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सकते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश

कुमार ने अस्वस्थता का हवाला दिया है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिवार के एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इसके चलते। कांग्रेस की हार को लेकर भड़के हैं इंडिया के घटक दल इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा था कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने

का कोई कार्यक्रम नहीं है। इतना ही नहीं कुछ दलों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने चार राज्यों के नतीजे आने के बाद सोमवार को कहा था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ कोई तालमेल नहीं कर अकेले चुनाव लड़कर गलती की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को दावा किया था कि तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस आत्ममुग्धता से पीड़ित है। उन्होंने कांग्रेस को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी आंतरिक कलह से निपटने की सलाह दी थी। बता दें कि इंडिया की अब तक तीस बैठक पटना, बंगलूरु और मुंबई में हो चुकी हैं। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक के बाद गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था।